■ वैशाख कृष्ण - 3 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 258 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » गुरुवार » 17-04-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

4 बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए : बागड़े

6 क्या तमिलनाडु में भाजपा व अन्नाद्रमुक पार्टी का साथ जीत की गारंटी बनेगा?

7 'करप्शन की करतूत को भी कुर्बानी का ताबूत' बना कर घूमती है कांग्रेस : नकवी

फर्स्ट टेक

इजराइली पासपोर्ट धारकों पर मालदीव ने लगाया प्रतिबंध

माले/एपी। मालदीव ने गाजा में युद्ध के कारण इजराइली पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश से रोकने के लिए अपने आव्रजन कानून में बदलाव किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, संशोधन को सोमवार को संसद द्वारा पारित किया गया और मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इसे मंजूरी दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून दोहरी नागरिकता वाले उन लोगों पर लागू होगा या नहीं जिनके पास इजराइल और किसी अन्य देश का पासपोर्ट है। मंत्रिमंडल ने आव्रजन कानून में बदलाव का निर्णय लगभग एक वर्ष पहले लिया था, लेकिन सरकार ने इस सप्ताह इसे औपचारिक रूप दिया।

गूगल ने भारत में 29 लाख विज्ञापन खाते निलंबित किए

नई दिल्ली/भाषा। इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने उसकी विज्ञापन नीति का दुरुपयोग करने के मामले में 2024 में भारत में 29 लाख विज्ञापनदाताओं के खाते निलंबित कर दिए और 24.74 करोड़ विज्ञापन हटा दिए। कंपनी ने बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। कंपनी ने अपनी वार्षिक विज्ञापन सुरक्षा रिपोर्ट में कहा, वैश्विक स्तर पर गूगल ने 3.92 करोड़ से अधिक विज्ञापनदाताओं के खातों को निलंबित किया। 5.1 अरब विज्ञापन हटा दिए और 9.1 अरब से अधिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट में कहा गया, '' भारत में 24.74 करोड़ विज्ञापन हटाए गए और 29 लाख विज्ञापनदाताओं के खाते निलंबित कर दिए गए।''

ईरान के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ का इस्तीफा

दुबई/एपी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने उन उपराष्ट्रपति में से एक के इस्तीफे को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जो दुनिया के ताकतवर देशों के साथ 2015 के परमाणु समझौते में तेहरान की ओर से प्रमुख वार्ताकार थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मंगलवार देर रात मोहम्मद जवाद जरीफ के संबंध में घोषणा ऐसे समय में आई है, जब ईरान अपने तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी कर रहा है। इस बीच, बुधवार से शुरू होने वाली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी की यात्रा में इस बात को लेकर वार्ता शामिल हो सकती है कि किसी प्रस्तावित सौदे के तहत उनके निरीक्षकों को क्या पहुंच मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमले करेंगे।

17-04-2025 सूर्यास्त 6:32 बजे | 18-04-2025 सूर्योदय 6:05 बजे

BSE 77,044.29 (+309.40) | NSE 23,437.20 (+108.65)

सोना 9,312 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 93,401 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

जिंदगी का मजहब

जिसे तुम मजहब कह रहे हो,
केवल वो ही सही नही है।
सभी जानते हैं इसके मायने,
बस तुम ने ही कही नहीं है।
ये जन्नत-मन्नत और चाहतें,
सच में किसी को रही नहीं है।
आदमी की जिंदगी है ये,
बनिये की खाताबही नहीं है।।

कांग्रेस ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोपपत्र को लेकर प्रदर्शन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने के विरोध में बुधवार को यहां प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुधवार को सुबह ही पार्टी के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंच गए और अपने नेताओं के पक्ष में और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही सरकार : खरगे

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली ''निरंकुश सरकार'' अपने ''पाप'' पर पर्दा डालने के लिए उनकी पार्टी को निशाना बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और वह सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''नरेन्द्र मोदी जी, आपकी निरंकुश सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाने पर तुली हुई है। भाजपा का आर्थिक कुप्रबंधन नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। हताशा बढ़ती जा रही है, कोई दृष्टि नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल ध्यान भटकाना।'' उन्होंने दावा किया कि व्यापार घाटा तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और 'टैरिफ' एवं व्यापार युद्ध पर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है तथा केवल खोखले शब्द और निरर्थक मुलाकातें हो रही हैं।

उच्चतम न्यायालय ने रखा

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

- कुछ प्रावधानों के ''गंभीर परिणाम'' हो सकते हैं, विशेष रूप से वे जो न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्तियों को कमजोर कर सकते हैं,
- पीठ ने अधिनियम को लेकर प्रावधान-वार आपत्तियों पर गौर किया और केंद्रीय वक्फ परिषद तथा राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने सहित कानून के कई पहलुओं पर आपत्तियां व्यक्त कीं।
- पीठ ने संशोधित कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाने का भी संकेत दिया, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने तक कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को विवादास्पद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने और केंद्रीय वक्फ परिषदों तथा बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने की शक्ति शामिल है।

शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका केंद्र ने विरोध किया तथा उसने ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश से पहले विस्तृत सुनवाई की अपील की।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता के खिलाफ 72 याचिकाओं से संबंधित सुनवाई प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हुई।

पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई जारी रखेगी। इसने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई और केंद्र से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम निकायों तथा व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सी यू सिंह सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने और एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा तथा कहा कि इससे ''समानताएं संतुलित होंगी''।

यह उल्लेख करते हुए कि कुछ प्रावधानों के ''गंभीर परिणाम'' हो सकते हैं, विशेष रूप से वे जो न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्तियों को कमजोर कर सकते हैं, प्रधान न्यायाधीश ने आदेश का प्रस्ताव रखा। पीठ ने कहा, ''अदालतों द्वारा वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को वक्फ के रूप में गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हों या विलेख द्वारा वक्फ हों, यद्यपि अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।''

पीठ ने संशोधित कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाने का भी संकेत दिया, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने तक कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।

पीठ ने अधिनियम को लेकर प्रावधान-वार आपत्तियों पर गौर किया और केंद्रीय वक्फ परिषद तथा राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने सहित कानून के कई पहलुओं पर आपत्तियां व्यक्त कीं।

इसने जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार देने तथा सक्षम न्यायालयों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''आमतौर पर, जब कोई कानून पारित होता है तो अदालतें प्रवेश स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं। लेकिन इस मामले में अपवाद की आवश्यकता हो सकती है। यदि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति को गैर-अधिसूचित किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।''

आगामी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

- एनएमएचसी परियोजना के विकास के दौरान लगभग 22,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

अहमदाबाद/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अहमदाबाद के निकट बनने वाला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) भारत की समुद्री धरोहर और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

जयशंकर ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक लोथल पुरातात्विक स्थल और निर्माणाधीन एनएमएचसी का दौरा किया। यह जगह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

एनएमएचसी का दौरा करने के बाद जयशंकर ने कहा कि ऐसा संस्थान समुद्री क्षेत्र में हमारे अनुसंधान, योजना और विमर्शों को आधार प्रदान करेगा।

जयशंकर ने 'एक्स' पर कहा, ''लोथल पुरातात्विक स्थल और निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया। यह परिसर हमारी समुद्री धरोहर के साथ-साथ आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे-जैसे हम विजन 'महासागर' को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संस्थान समुद्री क्षेत्र में हमारे शोध, योजना और विमर्शों को आधार प्रदान करेगा।''

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल में एक विश्व स्तरीय एनएमएचसी स्थापित कर रहा है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के विकास को मंजूरी दी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण एक ए के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि एनएमएचसी परियोजना के विकास के दौरान लगभग 22,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। एनएमएचसी के कार्यान्वयन से विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों, पर्यटकों और आगंतुकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, पर्यावरण और संरक्षण समूहों और व्यवसायों को काफी मदद मिलेगी।

अगले सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति बी आर गवई की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली/भाषा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति गवई मौजूदा सीजेआई के बाद उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वह 14 मई को 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति गवई को 24 मई, 2019 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल छह महीने से अधिक होगा और वह 23 नवंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। पिछले साल 11 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने आज केंद्रीय कानून मंत्रालय से न्यायमूर्ति गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की।

भूमि सौदे से संबद्ध धन शोधन मामला:

रॉबर्ट वाद्रा से दूसरे दिन भी हुई पूछताछ

नई दिल्ली/भाषा। कारोबारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाद्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वह पूर्वाह्न करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाद्रा भी थीं, जो केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं। रॉबर्ट वाद्रा के ईडी कार्यालय के अंदर जाने से पहले दोनों गले मिले। प्रियंका गांधी इस दौरान एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित एजेंसी के कार्यालय 'प्रवर्तन भवन' के आगंतुक कक्ष में रहीं और दोपहर करीब एक बजकर 10 मिनट पर उनके पति को दोपहर के भोजन अवकाश के लिए घर जाने की अनुमति मिलने पर उनके साथ चली गईं। सांसद को 'जेड प्लस' केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सुरक्षा प्राप्त है और इस दौरान सुरक्षाकर्मी बाहर इंतजार कर रहे थे। भोजन अवकाश के बाद भी पूछताछ जारी रहने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को वाद्रा से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गई।

अब अमेरिका ने चीन पर 245 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने कहा है कि चीन को अपनी जवाबी कार्रवाई के कारण अब अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' पर मंगलवार को अलग से दी जानकारी में कहा कि चीन ने बड़े बोइंग सौदे के तहत विमानों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

ये उन खबरों की पुष्टि करता है जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने अपनी विमान कंपनियों से अमेरिकी विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग से विमानों की आपूर्ति न लेने का कहा है। ट्रंप ने इस खबर की जानकारी देते हुए चीन जैसे अपने विरोधियों के साथ व्यापार युद्ध में अमेरिका और उसके किसानों की रक्षा करने का संकल्प लिया। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को जारी तथ्य पत्र में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आयातित प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण खनिजों तथा उनसे बने उत्पादों पर अमेरिकी निर्भरता से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की जांच शुरू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया, '' राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दिन ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाने के लिए अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका पहले) व्यापार नीति की शुरुआत की। 75 से अधिक देश पहले ही नए व्यापार समझौतों पर चर्चा करने के लिए समाने आ चुके हैं।

सैनिक गाजा, लेबनान, सीरिया में अनिश्चितकाल तक बने रहेंगे : इजराइल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरूशलम/एपी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि इजराइली सैनिक गाजा पट्टी में तथाकथित सुरक्षा क्षेत्रों, लेबनान और सीरिया में अनिश्चितकाल तक बने रहेंगे। रक्षा मंत्री के इस बयान से युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर हमास से जारी बातचीत की दिशा में फिर से जटिलता उत्पन्न हो सकती है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा में इजराइली हमलों में 22 अन्य लोग मारे गए, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है जो अभी एक साल की भी नहीं हुई थी। हमले में घायल हुई बच्ची की मां ने अपनी बेटी को दफनाए जाने से पहले उसे गले लगाया, जो अब भी खून से सनी नीली और सफेद पोशाक में थी।

पिछले महीने इजराइल द्वारा युद्धविराम समाप्त किए जाने के बाद हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव बनाने के वास्ते इजराइली बलों ने हाल के हफ्तों में गाजा के आधे से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।

रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने एक बयान में कहा, ''पूर्व की तरह (इजराइली सेना) उन क्षेत्रों से नहीं हटने जा रही है जिन्हें खाली करा दिया गया है और कब्जा कर लिया गया है।'' उन्होंने कहा, ''सेना लेबनान और सीरिया की तरह गाजा में किसी भी अस्थायी या स्थायी स्थिति में दुश्मन और (इजराइली) समुदायों के बीच सुरक्षा प्रदान करने के लिए ढाल के रूप में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी।''

इजराइल ने पिछले साल हिज्बुल्ला समूह के साथ युद्धविराम के बाद लेबनान के कुछ क्षेत्रों से हटने से भी इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति बशर असद को उखाड़ फेंकने के बाद उसने दक्षिणी सीरिया में एक 'बफर जोन' (संवेदनशील इलाकों को बाहरी दबावों से बचाने के लिए बनाया गया तटस्थ क्षेत्र) पर कब्जा कर लिया है।

उसका कहना है कि वह हमास के सात अक्टूबर, 2023 के हमले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखेगा।

'अमित शाह ने नहीं कहा कि यह गठबंधन सरकार होगी'

चेन्नई/भाषा। ऑल इंडिया द्रविड़ मनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई.के. पलानीस्वामी ने बुधवार को इस संभावना से इनकार किया कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन (जिसमें भाजपा प्रमुख घटक है) वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव जीतता है तो राज्य में गठबंधन सरकार बनेगी।

पलानीस्वामी ने पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी।

पलानीस्वामी ने कहा, ''उन्होंने ऐसा (गठबंधन सरकार के बारे में) नहीं कहा।'' पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रासंगिक मुद्दे को गलत समझा है जो (मीडिया) 'चालें' चलता है। पलानीस्वामी ने मीडिया से अपनी 'चालें' छोड़ने का अनुरोध किया।

पलानीस्वामी ने कहा कि शाह ने 11 अप्रैल को जो घोषणा की थी, वह यह थी कि अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनेगी, लेकिन इसका मतलब गठबंधन सरकार नहीं है। पलानीस्वामी ने गठबंधन के चुनाव जीतने पर भाजपा के साथ सत्ता साझा करने की गुंजाइश से इनकार किया

अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता ने कहा कि शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे और तमिलनाडु के मामले में इसकी कमान उनके हाथ में होगी। उन्होंने कहा, ''आपको समझना चाहिए, मामला स्पष्ट है।''

गोयल ने स्टारलिंक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, भारत में भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और भारत में अपनी मौजूदा साझेदारियों तथा भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा की।

गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' स्टारलिंक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की... जिसमें उपाध्यक्ष चाड गिब्स और वरिष्ठ निदेशक रयान गुडनाइट मौजूद रहे। चर्चा में स्टारलिंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंच, उनकी मौजूदा साझेदारियों और भारत में भविष्य की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई।''

उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने मार्च में भारत में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ एक समझौते की घोषणा की थी। दूरसंचार दिग्गज सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल ने भी स्पेसएक्स के साथ इसी तरह की साझेदारी की है।

सरकार ने 35 एफडीसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। शीर्ष औषधि नियामक संस्था सीडीएससीओ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे अस्वीकृत की गईं 35 'फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन' (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को रोकें जिनमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी पूरक आहार और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं।

एफडीसी दवाएं वे हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक फार्मास्युटिकल घटकों (एपीआई) का संयोजन होता है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को ऐसी एफडीसी के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा करने और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

नियामक ने यह निर्देश तब जारी किए जब उसने पाया कि कुछ एफडीसी दवाओं को सुरक्षा और प्रभावकारिता के पूर्व मूल्यांकन के बिना विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस दे दिया गया है, जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

ग्यारह अप्रैल को भेजे गए पत्र में भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव रघुवंशी ने जनवरी 2013 में उनके कार्यालय द्वारा जारी पत्र का हवाला दिया है, जिसमें डीसीजीआई से उचित अनुमोदन के बिना देश में ''नई दवा'' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली एफडीसी दवाओं की बिक्री के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। समय-समय पर यही चिंता जताई गई है और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को कई पत्र जारी किए गए हैं, जिन्होंने गैर-अनुमोदित एफडीसी के विनिर्माण और विपणन की अनुमति दी है। इस तरह का एक और पत्र इस वर्ष फरवरी में जारी किया गया था।

पत्र में कहा गया है, ''निदेशालय के संज्ञान में आया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत एनडीसीटी नियम 2019 के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा और प्रभावकारिता के पूर्व मूल्यांकन के बिना ही कुछ एफडीसी दवाओं को विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। इससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।''

नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम कर रही : साय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बुधवार को बस्तर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष 'प्रेरणा' में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें साय ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं बल्कि निरंतर गति की मांग करती है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और हर हितग्राही तक शासन की पहुंच सुनिश्चित हो। साय ने कहा कि बस्तर अब पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं बल्कि नए भारत की संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन रहा है और यहां का हर गांव, हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान, आधार, आवास और विद्युतीकरण जैसी योजनाएं केवल सरकारी परियोजनाएं नहीं, बल्कि आम जन की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी हैं। साय ने कहा, बस्तर के युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हम उन्हें सिर्फ कौशल नहीं, स्वाभिमान देना चाहते हैं। अब हमारा मंत्र है, हर घर में उजाला, हर हाथ में रोजगार और हर दिल में विश्वास। यही बस्तर की नई पहचान होगी और यहीं से छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम कर रही है।

इंदौर में पराली जलाने वाले किसानों पर लाखों रुपए का जुर्माना, कृषक संगठनों ने आपत्ति जताई

इंदौर/भाषा। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने खेतों में पराली (फसल अवशेष) जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए किसानों पर तगड़ा जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है और प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जिले में खेतों में पराली जलाने को लेकर अब तक 668 प्रकरण दर्ज किए हैं और संबंधित किसानों पर 13.68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारी के मुताबिक, प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है। यह आदेश पराली जलाने से पर्यावरण, आम लोगों और जीव-जंतुओं को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जारी किया गया है। अधिकारी ने बताया प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को 1 वर्ष तक के कारावास या 5,000 रु. तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन 'चोर मचाए शोर' जैसा: सचदेवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चोर मचाए शोर जैसा है।

इससे पहले दिन में कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र 'राजनीतिक प्रतिशोध' का कार्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दायर की गई एक याचिका का परिणाम है। कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार 2004 से 2014 तक केंद्र में सत्ता में थी। सचदेवा ने एक बयान में कहा, ''नेशनल हेराल्ड मामले में न केवल भ्रष्टाचार बल्कि विश्वासघात का भी गंभीर मामला है और इस पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ''चोर मचाए शोर'' जैसा है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय कांग्रेस नेता मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई नहीं है। अगर मामला कमजोर, झूठा या राजनीति से प्रेरित होता, तो गांधी परिवार, जो 2012 (जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी) से लेकर 2014 के मध्य तक सत्ता में था, अपने कार्यकाल के दौरान इसे रद्द करवा लेता।''

भारत के कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने बीते साल ढाई अरब डॉलर जुटाए : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) कंपनी ज़ेप्टो द्वारा जुटाए गए धन की बदौलत पिछले साल भारत के कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी (एग्रीफूडटेक) स्टार्टअप में निवेश तीन गुना होकर 2.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ऑम्निवोर ने वैश्विक निवेश मंच- एगफंडर के साथ मिलकर बुधवार को 'डेवलपिंग मार्केट्स एग्रीफूडटेक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के एग्रीफूडटेक स्टार्टअप में निवेश वर्ष 2024 में 2.5 अरब डॉलर का हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह निवेश 80.6 करोड़ डॉलर था। ज़ेप्टो ने पिछले साल कई दौर में 1.4 अरब डॉलर जुटाए थे। रिपोर्ट में कहा गया, ''भारत के लिए वर्ष 2024 में ई-किराना और रेस्तरां से संबंधित स्टार्टअप में निरंतर निवेश की बात सामने आती है, जो देश के घने शहरी परिवेश और उच्च जनसंख्या को देखते हुए उपयुक्त हैं।'' एक बयान के अनुसार, विकासशील बाजारों में कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी निवेश वर्ष 2024 में 3.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2023 से 63 प्रतिशत अधिक है और वैश्विक निवेश का 23 प्रतिशत है।

शीर्ष 10 देशों में से पाँच में निवेश बढ़ा : भारत 2.5 अरब डॉलर (+215 प्रतिशत), सिंगापुर 17.2 करोड़ डॉलर (+3 प्रतिशत), मेक्सिको 9.7 करोड़ डॉलर (+250 प्रतिशत), वियतनाम 8.7 करोड़ डॉलर (+350 प्रतिशत), और चिली 5.8 करोड़ डॉलर (+33 प्रतिशत)।

हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, लेकिन भाजपा का 'सड़ा हुआ' संस्करण स्वीकार्य नहीं : उद्धव ठाकरे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नासिक/भाषा। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा का त्याग नहीं किया है, लेकिन उनकी पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हिंदुत्व का 'सड़ा हुआ' संस्करण उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

ठाकरे ने उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना (उबाठा) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह भी सुझाव दिया कि राज्य की भाजपा-नीत सरकार को मुंबई में राजभवन परिसर को छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक में बदल देना चाहिए तथा राज्यपाल आवास किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। भाजपा से 2019 में अलग हो चुके ठाकरे ने कहा कि अविभाजित शिवसेना के बिना केंद्र और राज्य की मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाती कि अयोध्या में राम मंदिर बन सके। ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने झूठी कहानी फैलाई कि शिवसेना ने हिंदुत्व को त्याग दिया है। शिवसेना (उबाठा) ने कहा कि मुसलमानों ने उनकी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया।

यस बैंक को आयकर विभाग से 244 करोड़ रुपए का कर नोटिस

नई दिल्ली/भाषा। यस बैंक ने कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए 244.20 करोड़ रुपए का मांग नोटिस मिलने की बुधवार को जानकारी दी। बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, पुनर्मूल्यांकन आदेश में पुनर्मूल्यांकन आय तथा उस पर कर की गणना के लिए निर्धारित आय के बजाय आयकर रिटर्न में बताई गई आय पर विचार किया गया।

इसमें कहा गया, इस संबंध में 15 अप्रैल, 2025 को क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) ने नया आदेश पारित किया। यस बैंक ने कहा, ''उक्त सुधार आदेश के परिणामस्वरूप 244.20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर मांग उत्पन्न हुई है... बिना किसी ठोस वजह के इसकी काफी अधिक पुनर्गणना की गई है।'' इसमें कहा गया, इस आदेश के विरुद्ध बैंक तत्काल आधार पर जेएओ के समक्ष सुधार आवेदन दायर करेगा क्योंकि मांग निराधार प्रतीत होती है।

जेईई-मेन की अंतिम उत्तर कुंजी की प्रतीक्षा करें, निष्कर्ष न निकालें : एनटीए ने छात्रों से कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि इंजीनियरिंग के इच्छुक अभ्यर्थियों को जेईई-मेन की अंतिम उत्तर-कुंजियों का इंतजार करना चाहिए और अनंतिम उत्तर-कुंजियों में त्रुटियों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

एजेंसी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन के उत्तरों में कई त्रुटियों के बारे में शिकायतें मिलने की खबरों के बीच यह स्पष्टीकरण आया है। एजेंसी ने कहा, एनटीए ने हमेशा एक पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षार्थियों को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होते ही उनकी दर्ज की गई प्रतिक्रियाओं को देखने की अनुमति होती है। एनटीए अनंतिम उत्तर कुंजी को दी गई प्रत्येक चुनौती पर अत्यंत गंभीरता से विचार करता है।

एनटीए ने कहा, उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष व विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 'उत्तर कुंजी चुनौती' प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी विसंगति को दूर करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। एजेंसी ने कहा कि जेईई मेन्स की उत्तर कुंजी केवल अनंतिम हैं और अंतिम उत्तर कुंजी अभी प्रकाशित नहीं की गई है। एनटीए ने कहा, अंक केवल अंतिम उत्तर कुंजी के माध्यम से निर्धारित होते हैं। अनंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। एनटीए परीक्षार्थियों को सलाह देता है कि उन्हें उन खबरों से गुमराह नहीं होना चाहिए जिनमें अनावश्यक संदेह और चिंताएं जताई गई हैं।

आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया, राहुल के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों, विदेश नीति और आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के लिए उसके शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 'नेशनल हेराल्ड' मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, पिछले दो दिन से प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी देने की राजनीति जारी है। कांग्रेस नेतृत्व खासतौर पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों, विदेश नीति और आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है। रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संदर्भ देते हुए कहा कि इस प्रतिशोध की राजनीति के सूत्रधार दो व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया विफल हो गया तो अब फेक इन इंडिया के जरिए फर्जी विमर्श गढ़ा जा रहा है।

रमेश ने कहा, हमें चुप नहीं किया जा सकता। हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह इतना अजीबो गरीब मामला है कि एक रुपए का लेनदेन नहीं हुआ, लेकिन धनशोधन का आरोप लगा दिया गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह मामला तो दुनिया का आठवां अजूबा है।

ईडी ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोप-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की।

अहमदाबाद में कई वाहनों को टक्कर मारने पर टैक्सी चालक को भीड़ ने पीटा, मौत

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में आक्रोशित भीड़ की कथित पिटाई से उस टैक्सी चालक की मौत हो गई जिसकी टैक्सी कई वाहनों से टकरा गई थी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात जुहापुरा इलाके में हुई। चालक पर संदेह है कि वह नशे में था, जिसके कारण उसकी गाड़ी से कई दुर्घटनाएं हुईं।

पुलिस ने बताया कि पांच से छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि चालक की मौत भीड़ द्वारा पीटे जाने से हुई या किसी अन्य कारण से। उन्होंने बताया कि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (जोन 7) शिवम वर्मा ने बताया कि जान गंवाने वाला कौशिक चौहान (35) लापरवाही से टैक्सी चला रहा था, जिसके कारण रास्ते में उसकी टैक्सी कई वाहनों से टकरा गई। उन्होंने बताया कि जब उसकी टैक्सी से कई दुर्घटनाएं हो गईं तो कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और जुहापुरा में उसे पकड़ लिया। जुहापुरा अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता वाला क्षेत्र है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि एक टैक्सी चालक नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद आस-पास के लोग उसके पीछे दौड़े और उसे अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में पकड़ने में कामयाब हो गए और वहां उसकी उनसे हाथापाई हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे मृत पाया।

स्पाइसजेट पुनरुद्धार प्रक्रिया 'अच्छी चल रही', एक साल में बेड़े को दोगुना करेंगे: अजय सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। घरेलू एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने बुधवार को कहा कि कंपनी की पुनरुद्धार योजना 'बहुत अच्छी तरह से चल रही है' और एयरलाइन अगले 12 महीनों में अपने मौजूदा बेड़े को दोगुना करने की राह पर है।

जनवरी में, स्पाइसजेट ने अप्रैल के मध्य तक चार बोइंग बी 737 मैक्स सहित अपने 10 ठप विमानों को फिर से परिचालन में लाने की योजना की घोषणा की थी।

एयरलाइन ने कहा था कि उसने अक्टूबर, 2024 से अपने बेड़े में 10 विमान जोड़े हैं, जिनमें तीन ठप विमानों को फिर से सेवा में लाया गया और सात पट्टे पर शामिल किए गए।

स्पाइसजेट को वित्तीय संकट और विमान पट्टेदारों के साथ कानूनी विवादों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हाल के महीनों में, कंपनी ने धन जुटाया है और पुनरुद्धार के रास्ते पर है। यहां यात्रा सम्मेलन के दौरान स्पाइसजेट की पुनरुद्धार योजना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, यह बहुत अच्छी तरह से चल रही है और अगले साल तक हमें अपने वर्तमान बेड़े को दोगुना करने की उम्मीद है...फिलहाल हमारे सभी विमान ठप हैं, फिर भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं और अगले 12 महीनों में हम वर्तमान स्थिति से दोगुने हो जाएंगे। कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और काफी अच्छी तरह से पुनरुद्धार कर रही है।

स्पाइसजेट के बेड़े में 10 जनवरी तक कुल 62 विमानों में से 28 विमान परिचालन में थे, जिनमें 20 बी737, छह डी हैविलैंड कनाडा डीएचसी-8 डैश 8 और दो एयरबस ए320 शामिल थे।

इसके अलावा, जब अमेरिका के साथ चल रहे शुल्क युद्ध में चीन द्वारा अपने विमानन कंपनियों को बोइंग विमानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो स्पाइसजेट के सिंह ने कहा, हम विनिर्माताओं के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी स्थिति को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। हमें नहीं पता कि स्थिति क्या है। चीन को कितने विमान दिए जा रहे हैं और उन विमानों का क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि 'जो कुछ हुआ है, उससे हम जितना लाभ उठा सकते हैं, निश्चित रूप से हम ऐसा करेंगे।'

कठुआ मुठभेड़ से घुसपैठ का रास्ता पता चला, आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी: पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि कठुआ जिले में हाल में हुई चार मुठभेड़ों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पार से भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्ग का पता चल गया है। कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शोभित सक्सेना ने कहा कि मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों सहित गोला-बारूद की सफलतापूर्वक बरामदगी से जम्मू-कश्मीर में बड़े हमले की आतंकवादी समूहों की साजिश विफल हो गई।

पिछले एक महीने में कठुआ जिले में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह और सुरक्षा बलों के बीच चार मुठभेड़ें हुईं। सफियान जंगल में 27 मार्च को भारी हथियारों से लैस दो आतंकवादियों को मार गिराया गया था। हीरानगर सेक्टर के सानियाल जंगल में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में चार पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। एसएसपी ने राजबाग थाने में संवाददाताओं से कहा, हम चार में से शेष तीन आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं, जो मुठभेड़ से बच निकले हैं और भाग रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। थाने में अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित जब्त की गई सभी सामग्री प्रदर्शित की गई थी। जिले में सीमावर्ती गांवों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण आतंकवादियों के खिलाफ अभियान सफल हो रहे हैं। सक्सेना ने कहा, मुठभेड़ों ने उनके पारंपरिक (घुसपैठ) मार्ग को उजागर कर दिया है... हम उन्हें दोबारा इस मार्ग का उपयोग नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा बरामदगी से पता चलता है कि वे गलत इरादे से आये थे और उनकी मंशा लंबे समय तक यहां रहने की थी।

रामपुरा में रोड़ अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया मंत्री वी सोमन्ना ने

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तुमकुरु। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने तुमकुरु जिले के गुब्बी के पास डी. रामपुरा गाँव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) नंबर 62 के बदले में नवनिर्मित रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) को समर्पित किया और आज बांदीहल्ली रोड गेट पर आयोजित एक समारोह में बिल्लेपल्या (एलसी नंबर 50) और बांदीहल्ली रोड गेट (एलसी नंबर 60) पर दो आरयूबी के निर्माण की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने जोर देकर कहा कि डी. रामपुरा में नव उद्घाटन आरयूबी यात्रा के समय को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर क्षेत्र के निवासियों को काफी हद तक लाभान्वित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज जिन आरयूबी का शिलान्यास किया गया, वे इसी तरह जनता की सेवा करेंगे और क्षेत्र के विकास में योगदान देंगे।

सोमण्णा ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण की उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए रखे जाएं और परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों। उन्होंने ठेकेदारों को आरयूबी कार्य को इस तरह से निष्पादित करने का निर्देश दिया कि बारिश के मौसम में पानी का ठहराव न हो, जिससे दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर तुमकुरु शहर के विधायक ज्योति गणेश, मंडल रेल प्रबंधक अमितेश कुमार सिन्हा, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक परीक्षित मोहनपुरिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक कृष्ण चैतन्य और अन्य रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। नित्तूर और संपीगे रोड स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 62 (डी. रामपुरा गेट) के बदले में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण लगभग 6.37 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 7.88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल और मल्लासांद्रा और गुब्बी स्टेशनों के बीच स्थित एलसी नंबर 50 (बिल्लेपल्या गेट) के स्थान पर आरयूबी का निर्माण 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। ये रोड अंडर ब्रिज लेवल क्रॉसिंग पर लंबे इंतजार से बचकर यातायात के सुचारू प्रवाह में मदद करेंगे, जिससे निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और समग्र परिवहन दक्षता में योगदान मिलेगा।

अदालत ने 'मुडा' मामले में सीबीआई जांच को लेकर अर्जी पर सिद्दरामय्या, उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमयूडीए (मुडा) भूखंड आवंटन मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के अनुरोध संबंधी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की एक अर्जी पर बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या, उनकी पत्नी और अन्य को नोटिस जारी किया।

सिद्दरामय्या पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 भूखंडों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप हैं। अर्जी में एकल न्यायाधीश द्वारा सात फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की पीठ ने 28 अप्रैल तक जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, प्रतिवादियों को 28 अप्रैल तक जवाब के लिए नोटिस जारी किया जाता है। चूंकि यह कहा गया है कि संबंधित मामले से जुड़ी अपील उस दिन सूचीबद्ध की गई हैं। मूल याचिका इस वर्ष के प्रारंभ में खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि लोकायुक्त की जांच में कोई पक्षपात या विसंगति प्रदर्शित नहीं हुई। अदालत ने कहा था, लोकायुक्त की स्वतंत्रता संदिग्ध नहीं है।'' अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि संस्था की स्वायत्तता बरकरार है, जिसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने मान्यता दी है।

अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य से मामले को आगे ले जाने या फिर से जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने का आधार नहीं है। बुधवार की सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील के बारे में एक प्रक्रियात्मक प्रश्न उठाया। पीठ ने पूछा, यह तय करने के लिए क्या मानदंड हैं कि अपील स्वीकार्य है या नहीं? अपीलकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन ने स्पष्ट किया कि अर्जी में न्यायिक आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। अदालत ने संकेत दिया कि मामले के गुण-दोष पर आगे बढ़ने से पहले वह अपील के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर गौर करेगा। राघवन ने पीठ को यह भी बताया कि संबंधित अर्जियों पर 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है जिसमें प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा, यदि यह अदालत अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार कर लेती है तो मामले को सीबीआई को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता।

स्टार एयर ने बेंगलूरु से बीदर के लिए सीधी हवाई उड़ान शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बीदर। संजय घोडावत समूह की विमानन शाखा स्टार एयर ने कर्नाटक राज्य आरसीएस के तहत 16 अप्रैल से बेंगलूरु (बीएलआर) और बीदर (आईएक्सएक्स) के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के दूरदर्शी नेतृत्व में बुधवार को बीदर हवाई अड्डे पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली इस सेवा का शुभारंभ स्टार एयर द्वारा भारतीय वायु सेना, हवाई अड्डा संचालक जीएमआर, स्थानीय प्रशासन और स्टार एयर के अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। बेंगलूरु बीदर मार्ग यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करता है तथा क्षेत्रीय व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह नई सेवा, वंचित क्षेत्रीय क्षेत्रों को प्रमुख शहरी केंद्रों से जोड़ने के लिए स्टार एयर के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोप पत्र को सिद्दरामय्या ने मोदी-शाह की प्रतिशोध की राजनीति बताया

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। सिद्दरामय्या ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम बताता है कि वह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले असहमति के स्वरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर किया जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिशोध की राजनीति का एक और अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नागरिकों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय से इस तरह की घृणा की राजनीति का सामना कर रही है, एक बार फिर सत्य और न्याय की ताकत से जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने ईडी का लंबे समय से राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग किया है ताकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा सके। अब एक बार फिर 'नेशनल हेराल्ड' मामले में तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं के निराधार आरोपों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध की मुहिम चलाई जा रही है। सिद्दरामय्या ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने कहा, ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जांच के नाम पर बार-बार परेशान किया और मानसिक दबाव डाला।

'जाति आधारित गणना' कर्नाटक सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ अन्याय न हो : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्यया ने बुधवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में एक विशाल रोजगार मेले के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्ज्वलित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उपस्थित रहे।

कलबुर्गी / बेंगलूरु। सामाजिक-आर्थिक एवं शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति आधारित गणना) को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से बढ़ते विरोध के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई और 17 अप्रैल को होने वाली मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।

कर्नाटक के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत ने इस सर्वेक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसे 'अवैज्ञानिक' बताया है तथा मांग की है कि इसे खारिज किया जाए तथा नया सर्वेक्षण कराया जाए। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी इस पर आपत्ति जताई गई है तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से भी इसके खिलाफ तीखी आवाजें उठ रही हैं।

सिद्दरामय्या ने कलबुर्गी में संवाददाताओं से एक सवाल के जवाब में कहा, हमने बैठक बुलाई है। हम कल मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। यह एकमात्र विषय है जिस पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। यह वास्तव में एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण है, जाति आधारित गणना नहीं। हम इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे।

मंगलवार रात जाति आधारित गणना पर चर्चा के लिए उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व में वोक्कालिगा विधायकों की बैठक के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें ऐसा करने दें। उन्हें मंत्रिमंडल में अपनी राय साझा करनी होगी। पांच वोक्कालिगा मंत्री हैं। उन्हें रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपनी राय साझा करनी होगी।

उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक शमनुरु शिवशंकरप्पा के जाति आधारित गणना के खिलाफ बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, यह एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में लिंगायत समुदाय की जनसंख्या 66.35 लाख और वोक्कालिगा समुदाय की जनसंख्या 61.58 लाख बताई गई है। सिद्दरामय्या के नेतृत्व वाली अपनी ही पार्टी की सरकार को एक सख्त संदेश में शिवशंकरप्पा ने पूछा कि क्या सरकार का नेतृत्व करने वाले लोग वीरशैव-लिंगायतों और वोक्कालिगा के विरोध का सामना करते हुए अपना शासन जारी रख सकते हैं। शिवशंकरप्पा वीरशैव-लिंगायत समुदाय की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा, यदि वे (रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ने का) फैसला करते हैं, तो इसका उल्टा असर होगा... राज्य में प्रमुख समुदाय हैं - पहला वीरशैव और दूसरा वोक्कालिगा। क्या वे इन दो समुदायों के विरोध का सामना करते हुए अपना शासन जारी रख सकते हैं? हम (वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा) इकट्ठे एक साथ लड़ेंगे।

चन्नगिरी से कांग्रेस के एक अन्य विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने कहा कि जाति आधारित गणना रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और न ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे सभी विधायकों की एक बैठक बुलाकर इसके पक्ष-विपक्ष पर चर्चा करें और फिर इसे लागू करने पर निर्णय लें।

उन्होंने कहा, शिवशंकरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता ने समुदाय के पक्ष में बात की है और एक कड़ा संदेश दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं केवल अपने (वीरशैव लिंगायत) समुदाय के लिए नहीं बोलना चाहता, कई अन्य समुदाय भी अन्याय महसूस करते हैं। वीरशैव-लिंगायत मंत्रियों पर समुदाय के पार्टी विधायकों की बैठक न बुलाने के लिए निशाना साधते हुए शिवगंगा ने सरकार में सात लिंगायत मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की।

उन्होंने कहा, ''उनमें क्या नैतिकता है। मैंने चर्चा के लिए मंत्री ईश्वर खंड्रे को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। सात लिंगायत मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब समुदाय अन्याय का सामना कर रहा है, तो उनमें खड़े होने की क्षमता नहीं है...क्या उन्होंने अब तक कोई बैठक बुलाई है? वे स्वार्थी हो गए हैं।

मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम अब तो वे बैठक बुलाएं।'' प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदाय की शीर्ष संस्था वोक्कालिगा संघ ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे 'अवैज्ञानिक' बताया। उन्होंने राज्य सरकार से इसे खारिज करने और नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया है।

'कर्नाटक में बेरोजगारी कई राज्यों से कम'

कलबुर्गी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को दावा किया कि उनके राज्य में बेरोजगारी दर केवल 2.5 प्रतिशत है - जो कई अन्य राज्यों की तुलना में व देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्नाटक में निवेश के लिए कंपनियों को आकर्षित कर इसे और कम करने का प्रयास कर रही है। कलबुर्गी में कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रम बल सर्वेक्षण का हवाला दिया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 18.9 प्रतिशत डिग्री धारक और 17.1 प्रतिशत डिप्लोमा धारक बेरोजगार हैं। सिद्दरामय्या ने दावा किया, हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.04 प्रतिशत है, राजस्थान में 28.5 प्रतिशत, बिहार में 19.1 प्रतिशत और महाराष्ट्र में तीन प्रतिशत है। लेकिन कर्नाटक में यह केवल 2.5 प्रतिशत है।

उपाबंध-I

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-विधि के क्षेत्र में चुने हुए विषयों पर तथा अग्र निर्णयों पर चुने हुए लेखकों द्वारा संविदा के आधार पर हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकें लिखवाने के लिए आमंत्रण।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखवाए जाने हेतु आवेदन-

(1) विधि-शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया। (2) दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, लैंगिक अपराध, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण। (3) सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। (4) वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि। (5) पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तरराष्ट्रीय विधि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तरराष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधियां। (6) साइबर अपराध और कृत्रिम बौधिकता।

जीवन-वृतांत सहित आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञापन छपने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। 45 दिनों के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुस्तक लिखवाए जाने के संबंध में नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाइट www.lawmin.nic.in पर देखें तथा निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक),
विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग),
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन नं. 011-23387589, 23389001
फैक्स 011-23387589

(अविनाश शुक्ला)
प्रधान संपादक
मो. न. 9350585225
फोन नं. 23387589

CBC-24304/11/0003/2526

न्यायालय ने 'झोलाछाप चिकित्सकों' के अस्पतालों पर कार्रवाई का आदेश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें खुद को चिकित्सक के रूप में पेश करने वाले 'अयोग्य व्यक्तियों' (झोलाछाप डॉक्टर) द्वारा संचालित अस्पतालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने ऐसे अस्पतालों के, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, 'अनियंत्रित प्रसार' की आलोचना की और कहा कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अदालत ने कहा, ''ये झोलाछाप डॉक्टर खुद को चिकित्सक बताकर दूरदराज के क्षेत्रों में क्लीनिक चला रहे हैं और मरीजों को धोखा देकर निर्दोष ग्रामीणों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।'' न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस तरह की अवैध प्रथाओं के बढ़ने पर अंकुश लगाने में राज्य की स्पष्ट निष्क्रियता पर भी अविश्वास व्यक्त किया और इसे जानबूझकर अनजान' बने रहने का मामला बताया।

अदालत ने रजिस्ट्री को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को अपना आदेश भेजने का निर्देश दिया, जिसमें विभाग को अयोग्य व्यक्तियों' द्वारा संचालित अस्पतालों की पहचान करने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसने अदालत को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। यह निर्देश ए. ए. मुरलीधरस्वामी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 के तहत अपने अस्पताल के पंजीकरण की मांग की थी। हालांकि, मुरलीधरस्वामी के पास केवल एसएसएलसी की योग्यता है और वे सुनवाई के दौरान कोई वैध चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।हालांकि उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा करने के लिए 'खुद के योग्य' होने का दावा किया और भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा बोर्ड से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अदालत ने प्रमाणपत्र को संतोषप्रद नहीं पाया, क्योंकि उसमें चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाने वाले सबूत का अभाव था। उनके पास आवश्यक दवाओं के साथ सामुदायिक चिकित्सा सेवा में डिप्लोमा भी था, जिसके आधार पर वे कई वर्षों से मांड्या जिले में श्री लक्ष्मी क्लिनिक' नाम से एक अस्पताल चला रहे थे। पीठ ने पाया कि मुरलीधरस्वामी अस्पताल के एकमात्र संचालक, प्रशासक और कर्मचारी थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके वकील ने स्वीकार किया कि उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, चाहे वह एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या यूनानी। याचिकाकर्ता के चिकित्सक होने के दावे को साफ तौर पर 'गलत बयानी' करार देते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें राज्य के चिकित्सा नियमों के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं बनाती। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने कर्नाटक भोवी विकास निगम मामले में दूसरी गिरफ्तारी की

बेंगलूरु/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कर्नाटक के भोवी विकास निगम (केबीडीसी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है। केबीडीसी राज्य सरकार का विभाग है, जो भोवी समुदाय के कल्याण के लिए काम करता है। यह समुदाय कर्नाटक की अनुसूचित जाति (एससी) सूची में शामिल है।

ईडी ने एक बयान में बताया कि केबीडीसी की पूर्व प्रबंध निदेशक आर लीलावती को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने कहा कि उन्हें बेंगलूरु में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने मामले में इस महीने की शुरुआत में छापेमारी की थी और केबीडीसी के पूर्व महाप्रबंधक बीके नागराजप्पा को गिरफ्तार किया था। वह भी फिलहाल एजेंसी की हिरासत में हैं।

ईडी ने दावा किया कि लीलावती की नागराजप्पा, सुब्बाप्पा (केबीडीसी के तत्कालीन अधीक्षक) और अन्य संदिग्धों/आरोपियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी'' से बैंक खाते बनाकर केबीडीसी से धन के ''अंतरण'' में ''महत्वपूर्ण'' भूमिका थी। एजेंसी के मुताबिक, वे केबीडीसी के खातों से धनराशि को फर्जी कंपनियों/लाभार्थियों के खातों में भेजने में कामयाब रहे, जिसे बाद में इन आरोपियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मित्रों और परिवार के सदस्यों को अंतरित कर दिया गया। ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि कई बैंक खाते खोले गए और नागराजप्पा, लीलावती, सुब्बाप्पा और अन्य द्वारा जालसाजी करते हुए कई लाभार्थियों/इच्छित लाभार्थियों को धोखा'' दिया गया। धन शोधन का यह मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा केबीडीसी से 97 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और दुरुपयोग'' के आरोप में दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है।

गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई)
(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)
सी.वी. रमन नगर, पी.ओ. नं. 9302, बेंगलूरु - 560 093 ईमेल .: hrd.gtre@gov.in
फोन नं .: 080-25040894/25040895 फैक्स नं .: 080-25241507

अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति (2025-2026)

विज्ञापन सं. जीटीआरई/एचआरडी/026/2025-26 **दिनांक : 07 अप्रैल, 2025**

जीटीआरई अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	फैलोशिप की संख्या	रिक्तियों की संख्या	शैक्षिक योग्यता
तकनीकी स्ट्रीम (इंजीनियरिंग)			
1.	स्नातक अप्रेंटिस प्रशिक्षु	75	(बी.ई/बी.टेक/समकक्ष)
2.	डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षु	20	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
3.	आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षु	25	विभिन्न ट्रेड्स में आईटीआई
सामान्य स्ट्रीम (गैर-इंजीनियरिंग)			
4.	बी.कॉम	10	
	बी.एससी. (रसायन विज्ञान/ भौतिकी/गणित/ इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर)	05	
	बी.ए. (वित्त/बैंकिंग)	05	
	बीसीए	05	
	बीबीए	05	

आयु सीमा : न्यूनतम आयु - 18 वर्ष अधिकतम आयु - अनारक्षित श्रेणी - 27 वर्ष
(आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए ऊपरी आयु सीमा भारत सरकार के नियमों के अनुसार है)

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावित तिथि : 21 अप्रैल, 2025
ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की संभावित अंतिम तिथि : 08 मई, 2025
अधिक जानकारी और आवेदन पत्र (ऑनलाइन भरा जाना है) के लिए कृपया वेबसाइट - http://www.drdo.gov.in पर ''वॉट्स न्यू'' कैप्शन देखें।

CBC 10301/11/0007/2526 निदेशक, जीटीआरई

राज्य सरकार पुलिस को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए निरंतर उठा रही कदम : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस के जवानों के साहस, सेवा भावना और बलिदान को अतुलनीय एवं उन्हें सही मायनों में समाज के असली नायक बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार पुलिस को और अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। शर्मा बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक हैं। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान-माल की सुरक्षा करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पुलिसकर्मी अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए समर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को सात हजार रुपए से बढ़ाकर आठ हजार रुपए करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2400 रुपए से बढ़ाकर 2700 रुपए करने की घोषणा भी की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करएए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। हमारी सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की ढाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकथाम, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने सहित पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना भी है। शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है।

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और तकनीक के उपयोग से आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के हित में कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसी दिशा में पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 10 हजार पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, 5500 नवीन पदों का सृजन किया गया है तथा इस वर्ष 3500 नवीन पद सृजन प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि पद्मिनी कालीबाई एवं अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना के लिए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में एक हजार कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

साथ ही, पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं 250 लांगरी पदों का सृजन भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह नवाचार करती रहेगी। शर्मा ने कहा कि पुलिस मोबेलिटी के लिए लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं तथा आधुनिक उपकरणों के लिए 27 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने के लिए नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है।

वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आज प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। संस्कृत शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव कैलाश चंद यादव द्वारा जारी आदेशानुसार प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बोर्ड में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉ कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौर, नरेश चंद शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, प्रोफेसर हरेश्वर छिपा सहित कुल छह सदस्य बनाए गए है। बोर्ड राज्य सरकार द्वारा संभाग स्तर पर नवस्थापित किए जा रहे आदर्श वेद विद्यालय तथा तीन वैदिक गुरुकुल सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों और वेद पाठशालाओं का संचालन करेगा एवं उनके पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली का संचालन करेगा।

नेशनल हेराल्ड केस : विरोध प्रदर्शन पर राठौड़ ने गांधी परिवार को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा गांधी परिवार के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने कांग्रेस को शाही परिवार बताते हुए कहा कि जैसे ही यह परिवार नेशनल हेराल्ड केस में फंसता है, वैसे ही बौखला जाता है।

राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहाकि जब भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा जाता है, तो उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा डगमगाने लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है? राठौड़ ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास बताया और कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला है, जिसमें गांधी परिवार की भूमिका संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा पेश की गई चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन्हें कांग्रेस नजरअंदाज नहीं कर सकती। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह मामला देश के करोड़ों लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को इसका जवाब देना ही होगा।

राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह न्याय प्रक्रिया में सहयोग करे और जनता के सामने सच्चाई लाए।

बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि शिक्षा के तहत बच्चों को चुनौतियों से लड़ने वाला मन बनाने का कार्य किया जाए। बागड़े बुधवार को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, सेवा भारती और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में शिक्षा में जो बजट आवंटित किया है वह विद्यार्थियों के विकास के लिए है। शिक्षा से विद्यार्थी का मन विकसित होता है तो अपने आप ही आपदाओं से जूझने के लिए समाज तैयार होगा।

बागड़े ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के तहत मन, आचार, विचार भी विकसित होंगे। उन्होंने विनोबा भावे के कथन की चर्चा करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ और देश का झंडा बदला गया तभी शिक्षा नीति भी बनानी चाहिए थी, लेकिन यह बदली नहीं, इसलिए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ी। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है वह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से और उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'मानव जोड़ो, आदमी जोड़ो' की शिक्षा दी है। इस शिक्षा का अर्थ है, मन से लोगों से संबंध बनाएं। देश प्रेम से युवा पीढ़ी जुड़े। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता बढ़े। इसलिए आदमी जोड़ने का कार्य हो। आदमी जोड़ने का अर्थ है, भारत को एक सूत्र में बांधा जाए।

बागड़े ने नकल मुक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तभी यह संभव हो सकेगा। उन्होंने रटाने की बजाय मन से पढ़ने, पढ़ाने के लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वही ज्ञान सार्थक है जो समय के साथ प्रासंगिक रहे। नयी शिक्षा नीति इसी आधार पर तैयार की गयी है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का वह आलोक है, जिसमें जीवन की तमाम आपदाओं से मुकाबला करने की दृष्टि है।

उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आपदा के बाद पुनर्वास के तरीके भी बताए गए हैं। कार्यशाला के आरंभ में बागड़े ने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने वाली संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय ग्रंथों में बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा में भूस्खलन से बचाव के लिए उचित स्थान पर घर बनाना, बाढ़ से बचाव के लिए बांध और नहरें बनाना और सूखे से बचाव के लिए पानी के संरक्षण की परंपराएं हमारे यहां आपदा प्रबंधन रूप में ही बनी। उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यशाला

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत एक विशेष कार्यशाला में भाग लेते हुए

मध्य प्रदेश में जैन मुनियों पर हमले से नाराज समाज, जोधपुर में मौन जुलूस निकाला

जोधपुर । मध्य प्रदेश के सिंगोली में जैन साधुओं पर हुए हमले के बाद जैन समाज में आक्रोश है। राजस्थान के जोधपुर में जैन समाज के लोगों ने बुधवार को मौन जुलूस निकाला और संतों को सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जैन मुनियों के लिए पुलिस सुरक्षा और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

सिंगोली में जैन मुनियों पर हमले की घटना के विरोध में बुधवार को जोधपुर में जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध दर्ज किया। साथ ही जैन समाज ने मांग की कि जैन मुनियों के विहार के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। समग्र जैन समाज संस्था के आह्वान पर निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुईं। यह जुलूस सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जुलूस से पहले जैन समाज के लोग महावीर कॉम्प्लेक्स के बाहर एकत्र हुए और यहां से जुलूस के रूप में हाथों में तख्तियां लेकर रवाना हुए। तख्तियों पर जैन संतों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लिखी गई थी। जुलूस सोजती गेट से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का हल्लाबोल, अशोक गहलोत बोले- 'लोकतंत्र की हत्या हो रही है'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर में बुधवार को एक लोकतांत्रिक दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। जबकि सच्चाई यह है कि इसी मामले में पहले जांच हो चुकी है और कांग्रेस नेतृत्व को क्लीन चिट मिल चुकी है। यह सिर्फ एक झूठे आरोप को दोहराने की कोशिश है। हमारा संघर्ष सच्चाई के लिए है, लोकतंत्र के लिए है।

टीकाराम जूली ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा, यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं, बल्कि एक नॉन-प्रॉफिट संस्था का मामला है। कोई लेन-देन नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कहा, यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। हम न्यायपालिका में आस्था रखते हैं और कानून के दायरे में रहकर इसे सुलझाएंगे। सोनिया गांधी जी की छवि खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, देश की जनता उसे समझती है। वहीं, राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के घोटालों के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईडी अपनी जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए।

दो वर्षों में संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को करें पूरा : शर्मा

जयपुर/दक्षिण भारत । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रेल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी पर बने हुए चार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि चूरू, जैसलमेर और बीकानेर जिले में पेयजल उपलब्धता में अभिवृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की समीक्षा करते हुए कहा कि फव्वारा सिंचाई पद्धति को विशेष रूप से विकसित किया जाए। उल्लेखनीय है कि महाराजा गंगासिंह ने वर्ष 1927 में गंगनहर की शुरुआत की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री के शिवपुर हैड निरीक्षण के दौरान वर्ष 2027 में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाने का फैसला लिया गया है।

बाल विवाह पर प्रशासन सख्त

डीग/दक्षिण भारत। आखातीज, पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों व अन्य पर्वों पर बाल विवाह को रोकने के संबंध में गृह विभाग राजस्थान सरकार के 27 फरवरी 2025 में दिए गए निर्देशों की पालना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवी सिंह द्वारा जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय में बैठक आयोजित करने तथा उनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए। ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो बाल विवाह संपन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैंड बाजा, पंडित, बाराती, टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन और उन्हें कानून की जानकारी देने की निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन, ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्रवाई करना, विद्यालयों में बाल विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी, सामूहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गांव मोहल्ले में उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका है, उन्हें समझाइश करते हुए और यदि आवश्यकता हो तो कानून द्वारा बाल विवाह को रोके जाने के निर्देश दिए गए। विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधु के आयु का प्रमाण प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पर वर-वधु की जन्म तारीख आवश्यक रूप से प्रिंट किए जाने के निर्देश दिए गए है।

सिल्क्यारा सुरंग में सफलता मिली, धामी ने कहा- इसका नामकरण बाबा बौखनाग के नाम पर होगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिल्क्यारा (उत्तराखंड)/भाषा। 'सिल्क्यारा बेंड-बरकोट रोड' सुरंग में दोनों तरफ से खुदाई पूरी होने के साथ बुधवार को बड़ी सफलता मिली। इसी सुरंग में 2023 में 41 श्रमिक दो सप्ताह से अधिक समय तक फंसे रहे थे।

सफलता मिलने पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस दिन सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाग मंदिर का अभिषेक समारोह भी हुआ। दोनों समारोहों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2023 में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाबा बौखनाग के आशीर्वाद के कारण बचाया जा सका और देवता के नाम पर सुरंग का नाम बदलने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

धामी ने सुरंग स्थल पर दोनों कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में उपस्थित लोगों से कहा, ''बाबा बौखनाग की पूजा करने के केवल तीन दिन बाद, दुनिया के सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान में सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से संभव हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।'' उन्होंने लंबे समय तक जारी बचाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनको भी धन्यवाद दिया।

चार धाम यात्रा के मद्देनजर 4.531 किलोमीटर लंबी यह सुरंग काफी महत्वपूर्ण है। दो लेन की दो दिशा वाली इस सुरंग का निर्माण लगभग 853 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।

धामी ने कहा कि सुरंग के पूरा होने पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में केवल पांच मिनट लगेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।''

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के एमडी कृष्ण कुमार ने कहा कि सुरंग को पूरी तरह से चालू होने में लगभग 15-18 महीने और लगेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 के भूस्खलन के बाद 17 दिनों की कठिन परीक्षा से गुजरने वाले 41 श्रमिकों में से 15-16 अब भी सुरंग में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित निकालने से लेकर सुरंग का काम पूरा होने तक यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर, 2023 को श्रमिक उसके अंदर फंस गए थे। उन्हें 28 नवंबर को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था।

ममता ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया, उन्हें 'सबसे बड़ा भोगी' बताया

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की आलोचना करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उन्हें ''सबसे बड़ा भोगी'' करार दिया।

यहां इमामों और धर्म गुरुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख बनर्जी ने आदित्यनाथ पर अपने राज्य के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कानून-व्यवस्था, विशेषकर धार्मिक आयोजनों के दौरान उनके कामकाज की आलोचना की। बनर्जी ने कहा, ''योगी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वह सबसे बड़े 'भोगी' हैं। महाकुंभ भगदड़ में कितने लोग मारे गए? क्या उन्होंने सही आंकड़े साझा किए कि इसमें कितने लोग मारे गए? उप्र में पुलिस मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए। वह शांतिपूर्ण रैलियां भी नहीं करने देते।'' उनकी टिप्पणी उप्र के मुख्यमंत्री द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि ''बंगाल जल रहा है और बनर्जी हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं।'' दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई का आह्वान करते हुए आदित्यनाथ ने कहा था, ''लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।''

मुर्शिदाबाद दंगे पूर्व नियोजित थे, भाजपा, बीएसएफ, केंद्रीय एजेंसियों ने भड़काई हिंसा: ममता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को बुधवार को पूर्व नियोजित करार दिया और साथ ही सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक वर्ग, गृह मंत्रालय के तहत आने वाली केंद्रीय एजेंसियों तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया।

ममता बनर्जी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दमनकारी वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि यह कानून देश को विभाजित करेगा। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया और उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने दावा किया कि पड़ोसी बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के बावजूद केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को जल्दबाजी में पारित कर दिया और अवैध सीमा पार से घुसपैठ की अनुमति दी, जिसके कारण बंगाल में अशांति फैली। ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ के एक वर्ग और गृह मंत्रालय के अधीन कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने हिंसा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ''मुझे ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें मुर्शिदाबाद में अशांति के पीछे सीमा पार से आए तत्वों की भूमिका का दावा किया गया है। क्या सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका नहीं है?

असम में कानून व्यवस्था की स्थिति परेशान करने वाली : गौरव गोगोई

गुवाहाटी/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई ने बुधवार को आरोप लगाया कि असम की कानून-व्यवस्था में 'परेशान करने वाली गिरावट' देखी जा रही है और यह एक पुलिस राज्य बन गया है, जहां 'धमकाना और न्याय में चूक आम बात हो गई है।' लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने पार्टी प्रवक्ता रीतम सिंह से मिलने के बाद यह टिप्पणी की। रीतम सिंह राज्य भर में दर्ज विभिन्न मामलों में कई बार गिरफ्तार होने के बाद वर्तमान में मोरीगांव जिला जेल में बंद हैं। गोगोई ने पोस्ट में कहा, ''पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक मामले में फंसाया जा रहा है। मैं उनसे मिलने और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कल मोरीगांव जिला जेल गया था।'' सांसद ने बताया कि चूंकि यह असमिया नववर्ष माह बोहाग का पहला दिन था, इसलिए उन्होंने सिंह को कुछ 'पीठा' और अन्य पारंपरिक मिठाइयां भेंट कीं। जोरहाट से लोकसभा सदस्य गोगोई ने कहा, असम में कानून और व्यवस्था परेशान करने के स्तर तक ध्वस्त हो गई है। यह एक पुलिस राज्य बन गया है, जहां धमकी और न्याय का हनन आम बात हो गई है।

ईडी को भंग कर देना चाहिए, आर्थिक अपराधों की जांच के लिए अन्य एजेंसियां हैं: अखिलेश यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराधों की जांच के लिए अन्य एजेंसियां भी हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जाते समय भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने प्रवर्तन निदेशालय बनाया था और अब उसे इसी एजेंसी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस द्वारा इस जांच एजेंसी के खिलाफ किए गए देशव्यापी प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''मैं नेशनल हेराल्ड के बजाय ईडी पर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस ने ईडी को बनाया और अब उसी संगठन के कारण वह मुश्किल में है। मैंने पहले एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से कहा था कि आर्थिक अपराधों की जांच के लिए आयकर विभाग जैसी कई संस्थाएं हैं। इसलिए ईडी की कोई जरूरत नहीं है। इसे भंग कर देना चाहिए।'' प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप-पत्र दायर किया है, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपए के धनशोधन का आरोप लगाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'डबल इंजन' शासन मॉडल की सफलता के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोनों इंजन अलग-अलग लाइन में चल रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं नहीं जानता कि ओडिशा में क्या हो रहा है। राज्य और केंद्र में समन्वित शासन अपने अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है।''

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा पर भाजपा के आरोपों पर यादव ने कहा, ''ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं और मेरा मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में अशांति पैदा करना पसंद नहीं करेगी।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। कन्नौज और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर भाजपा के सदस्यों ने मंदिरों में मांस रखा और दंगे किए। भाजपा लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।''

इस बीच, यादव ने शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सपा ओडिशा में अपने संगठन का विस्तार करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा, ''हम जमीनी स्तर पर अधिक लोगों से जुड़कर ओडिशा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।''

कांग्रेस नेता से अपनी मुलाकात के बारे में यादव ने कहा, ''बाबासाहेब अंबेडकर के समानता, सम्मान और समावेशिता के सपने को पूरा करने के लिए मैं यहां जेना से मिलने आया हूं, जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक हैं। अंबेडकर के सपने के साथ सपा का लक्ष्य ओडिशा में विस्तार करना है।''

विपक्षी दलों ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं करने पर सवाल उठाया।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने की मांग की और दंगों को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, ''हम मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं, जो जेहादी तत्वों के हमलों से लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही हैं। हिंदू होने के कारण पिता-पुत्र की जेहादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये जेहादी तत्व राज्य में खुलेआम घूम रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची जिसके कारण हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घरों और संपत्तियों को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे हिंसा के दौरान प्रशासन की ''निष्क्रियता'' का पता चलता है।

नंदीग्राम से भाजपा विधायक ने कहा, ''मुख्यमंत्री हिंसा के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय एजेंसियों को दोषी ठहरा रही हैं, लेकिन वास्तव में उनकी पुलिस और प्रशासन हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहा तथा उत्पात जारी रहने दिया। दूसरी ओर, यह सीमा सुरक्षा बल ही था जिसने हस्तक्षेप किया और हालात को बिगड़ने से रोका। उन्हें (ममता) सच बोलने का साहस दिखाना चाहिए।''

बनर्जी द्वारा उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाए जाने पर अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने पहले भी मुझ पर इसी तरह आरोप लगाया था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है।''

दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई में केवल कांग्रेस ही आरएसएस-भाजपा को हरा सकती है: राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मोडासा (गुजरात)/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता भले ही हतोत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन केवल उनकी पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा को हरा सकती है।

एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद ने राज्य में संगठन को नया रूप देने के लिए रोडमैप पेश किया और पार्टी के उन नेताओं को हटाने का वादा किया जो या तो निष्क्रिय हैं या भाजपा के लिए काम करते हैं। उन्होंने कभी अपना गढ़ रहे गुजरात को अपनी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा 30 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने का संकल्प व्यक्त किया। गांधी गुजरात में संगठन को नया रूप देने के कांग्रेस के प्रयासों के तहत जिला इकाइयों को मजबूत करने की प्रायोगिक योजना शुरू करने के बाद अरवल्ली जिले के मोडासा शहर में बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

एक एआईसीसी पर्यवेक्षक और चार राज्य पर्यवेक्षकों समेत पांच सदस्यों वाली एक समिति गुजरात में पार्टी की 41 जिला इकाइयों (आठ शहरों समेत) में से प्रत्येक के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया की देखरेख करेगी, जिसकी शुरुआत अरवल्ली जिले से होगी।

अपने संबोधन में गांधी ने कार्यकर्ताओं से कई वादे किए जैसे कि जिला इकाइयों को अधिक शक्ति एवं धन उपलब्ध कराना, वरिष्ठ नेताओं-कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करना, जमीनी स्तर पर सक्रिय पदाधिकारियों को बढ़ावा देना और उन नेताओं को हटाना जो या तो निष्क्रिय हैं या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, यह विचारधाराओं की लड़ाई है। केवल दो ही पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं हैं - एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। केवल कांग्रेस ही भाजपा और आरएसएस को हरा सकती है। गुजरात पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि भाजपा की हार का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा, एक तरह से, कांग्रेस गुजरात में अस्तित्व में आई क्योंकि पार्टी के दो महान नेता - महात्मा गांधी और सरदार पटेल - इसी राज्य से थे।

गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता 'हताश' हैं, क्योंकि कांग्रेस लगभग तीन दशकों से राज्य में सत्ता से बाहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि यहां भाजपा को हराना मुश्किल है। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि भाजपा को हराना आसान है और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। हमें पार्टी की कार्यप्रणाली में बस कुछ बदलाव की जरूरत है। स्थानीय नेताओं ने, नेताओं के बीच विनाशकारी प्रतिस्पर्धा और स्थानीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना चुनाव टिकटों का बंटवारा जैसे कुछ मुद्दों को उजागर किया है।

उत्तर प्रदेश: दलित समुदाय के लोगों पर हमले से गांव में तनाव

एटा/भाषा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा खंडित किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोहनपुर गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि लोधी समुदाय के कुछ बदमाश मंगलवार रात पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्ती उनके घरों में घुस गए और महिलाओं एवं बच्चों सहित लोगों से मारपीट की।

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय से मदद की गुहार लगाई। भीम आर्मी की जिला इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र भास्कर ने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि लोधी समाज के लोगों ने दलित व्यक्तियों पर प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात की गई है।

अतिक्रमण का जवाब सिर्फ बेदखली है, मुआवजा नहीं: अरूणाचल राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल के. टी. परनाइक ने बुधवार को कहा कि मुआवजा नहीं, बल्कि बेदखली ही इसका एकमात्र समाधान है। आरक्षित वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की पहल की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इसके क्रियान्वयन में गंभीरता और दक्षता दिखाएं।

परनाइक ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ''हरित राज्य'' है और यहां के वनों को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने एआई उपकरणों और उपग्रह मानचित्रण की मदद से आरक्षित वनों की नियमित निगरानी तथा इनके संबंध में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एनई-एसएसी) की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की वकालत की। राज्यपाल ने कहा कि भूमि या वन मंजूरी में देरी के कारण कोई भी कल्याणकारी परियोजना रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने पर्यावरण एवं वन विभाग, राजधानी क्षेत्र और पापुम पारे जिला प्रशासन तथा ईटानगर नगर निगम से होलोंगी हवाई अड्डे से राज्य की राजधानी तक सड़क किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू करने को कहा।

उत्तर प्रदेश: भीख मांगकर कैंसर पीड़ित महिला की मदद का उठाया बीड़ा

शाहजहांपुर/भाषा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में समाजसेवी सलमान ने कैंसर से पीड़ित महिला के इलाज के लिए भीख मांगकर मदद करने का बीड़ा उठाया।

शाहजहांपुर के रोशनगंज मोहल्ले में रहने वाले संजीव कुमार ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उनकी पत्नी को गले का कैंसर है और पिछले आठ महीने से लगातार वह इलाज करा रहे हैं लेकिन इलाज में बेटी की शादी के लिए इकट्ठा की गई करीब छह लाख रुपए की जमापूंजी खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा और प्रतिदिन 700 रुपए इलाज में खर्च हो रहे हैं तथा उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। कुमार ने बताया कि वह जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों से मिले लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।

सुरुचि सिंह ने लगातार दूसरे विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को रजत पदक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लीमा (पेरू)/भाषा। युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने यहां 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आईएसएसएफ विश्व कप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता मनु भाकर ने रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में भारत का दबदबा सुनिश्चित किया।

ब्यूनस आयर्स में हाल में साल के पहले विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा के झज्जर की निवासी 18 वर्षीय सुरुचि ने 24 शॉट के फाइनल में 243.6 का स्कोर बनाकर मनु को 1.3 अंक से पीछे छोड़ा। चीन की याओ कियानक्सुन ने कांस्य पदक जीता।

सुरुचि और मनु के पोडियम पर पहुंचने का मतलब था कि भारत ने इस दिन प्रत्येक रंग का एक पदक जीता, जिसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के निशानेबाज सौरभ चौधरी का कांस्य पदक भी शामिल है। पेरू की राजधानी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन के कारण भारत तीन पदकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। उसके बाद चीन का नंबर आता है जिसने पुरुषों की एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में 60 शॉट के क्वालीफिकेशन राउंड में सुरुचि ने 582 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया था जबकि मनु ने 578 अंक बनाकर चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। भारत की एक अन्य निशानेबाज सैन्यम 571 अंक के साथ 11वें स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक में महिला एयर पिस्टल और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मनु ने कहा कि वह भारतीय निशानेबाजों की प्रगति से खुश हैं और उन्होंने सुरुचि को उनके दूसरे विश्व कप स्वर्ण पदक के लिए बधाई भी दी।

उन्होंने कहा, '' मैं यह देखकर खुश हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक भारतीय निशानेबाज आगे आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।''

'एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी' : चेतेश्वर पुजारा की पत्नी ने लिखे अपने संस्मरण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अपनी तरह के अनूठे संस्मरण में भारत के अनुभवी क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने जीवन के अनुभव कलमबद्ध किये हैं जिनमें मैदान के भीतर और बाहर के उतार चढावों और क्रिकेट के दीवाने देश में अपार अपेक्षाओं के बारे में बेबाक ढंग से लिखा है ।

हार्परकोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित यह किताब ' द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ : अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर' को पूजा और नमिता काला ने लिखा है जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा । पूजा ने एक बयान में कहा ,'' चेतेश्वर पुजारा जिद्दी लेकिन सहयोग करने वाले इंसान है जो ज्यादा बोलते नहीं लेकिन उनके पास छिपाने के लिये भी कुछ नहीं है । वह आध्यात्मिक हैं लेकिन पाखंडी नहीं और उन्हें मूर्खतापूर्ण लतीफे सुनाना पसंद है । राजकोट की गलियों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक उनका सफर अनूठा रहा है और मुझे इसे करीब से देखने का मौका मिला है।'' उन्होंने कहा ,'' मेरा विश्वास है कि चेतेश्वर पुजारा की कहानी में सभी के लिये कुछ न कुछ है और यही वजह है कि मैने यह किताब लिखी ।''

जीवन में कभी क्रिकेट नहीं देखने वाली पूजा पाबारी ने 2013 में चेतेश्वर पुजारा से शादी की और उसके बाद से एक क्रिकेटर के दैनंदिनी जीवन का उन्हें अनुभव मिला।

सुविचार

सफलता का मार्ग और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसा है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

नवाचार का उत्सव बने मानसून

गर्मी का मौसम, महंगाई, कई इलाकों में पेयजल की समस्या के बीच मौसम विज्ञान विभाग द्वारा की गई घोषणा कि 'इस बार मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है', राहत की खबर है। भारत में कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर करता है। अगर मानसून समय पर आ जाए तो गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है, खाद्यान्न की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, शहरों की ओर पलायन भी कम होता है। यह अनुमान इस लिहाज से भी खास है, क्योंकि इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'टैरिफ के बम' फोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए अच्छा मानसून खुशहाली का संकेत है। चूंकि मौसम विज्ञान विभाग ने सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है, इसलिए हमें आसमान से बरसने वाले अतिरिक्त अमृत को सहेजने और उसके सदुपयोग के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। हर शहर और गांव में नालियों की सफाई का ध्यान रखना होगा। पानी की निकासी का इंतजाम समय से पहले कर दिया जाए तो हादसों की आशंका कम होगी। इसके अलावा, जहां कहीं बिजली के खंभे, खुले तार आदि हैं, वहां सुरक्षा संबंधी कदम जरूर उठाने चाहिएं। हर साल बारिश के मौसम में कई लोगों की मौत करंट लगने से होती है। अगर स्थानीय प्रशासन थोड़ी-सी सावधानी बरत ले तो ऐसे हादसों को टाल सकता है। मानसून आने से पहले, पिछले दस वर्षों में हुए वर्षाजनित हादसों का अध्ययन करें। अब तो एआई आधारित सुरक्षा मॉडल की मदद ली जा सकती है। उसके जरिए भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए अधिकारी हादसों का इंतज़ार न करें, उन्हें टालने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें।

हमारे देश में हर जगह की कृषिभूमि के साथ कई खूबियां जुड़ी हैं। अगर खेत में फसल बोने से पहले इस बात की सही जानकारी मिल जाए कि मिट्टी में किन तत्त्वों की कमी या अधिकता है, कौनसी फसल अच्छी हो सकती है, तो किसानों को बहुत फायदा होगा। मानसून के दस्तक देने से पहले ही गांवों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि किसान अपने खेत की मिट्टी का आसानी से परीक्षण करवाकर पर्याप्त जानकारी हासिल कर सकें।

हमारे देश में हर जगह की कृषिभूमि के साथ कई खूबियां जुड़ी हैं। अगर खेत में फसल बोने से पहले इस बात की सही जानकारी मिल जाए कि मिट्टी में किन तत्त्वों की कमी या अधिकता है, कौनसी फसल अच्छी हो सकती है, तो किसानों को बहुत फायदा होगा। मानसून के दस्तक देने से पहले ही गांवों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि किसान अपने खेत की मिट्टी का आसानी से परीक्षण करवाकर पर्याप्त जानकारी हासिल कर सकें। उन्हें उन्नत बीजों, बढ़िया खाद, सिंचाई के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाए। आज रसायन-युक्त खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरता घट रही है। वहीं, जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाल में सरकार ने कुछ किसानों को पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जो ग्रामीणों को ऐसी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके अनुभवों का प्रचार किया जा सकता है। भारत एक विशाल देश है, लेकिन यहां कृषि योग्य भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हमें इज़राइल के अनुभवों से सीखना चाहिए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा देश है, जबकि वह खेती और बागवानी करने के लिए अपने संसाधनों का बहुत कुशलतापूर्वक उपयोग करता है। वहां कई घरों, दफ्तरों, सार्वजनिक महत्त्व की इमारतों पर सब्जियां उगाई जाती हैं। इज़राइल उन इमारतों की दीवारों का भी पूरा उपयोग करता है। क्या हम अपने देश में ऐसा नवाचार नहीं कर सकते? यहां तो जगह की कोई कमी नहीं है। अगर लोगों को थोड़ी-सी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इससे लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और पोषण के स्तर में बढ़ोतरी होने से देश भी सशक्त होगा। हम मानसून को नवाचार का उत्सव बनाएं।

ट्वीटर टॉक

नेशनल हेराल्ड केस में कोई दम नहीं है।यह मामला राजनीति से प्रेरित है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को निशाना बनाया गया।

-सचिन पायलट

जयपुर की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए नागरिकों व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि हेरिटेज सिटी की गरिमा बनी रहे ।

-दीया कुमारी

आज दिल्ली में मेक माय ट्रिप के ट्रैवल एंड टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी कॉनक्लेव 2025 में शामिल होकर इस क्षेत्र विशेष में मोदी जी के नेतृत्व की प्राथमिकताओं और नीतियों पर बात रखी। आज सकारात्मकता का एक अभूतपूर्व माहौल है।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

प्रेरक प्रसंग

ईमानदारी के नमक से प्रसाद

एक बार एक पर्व पर स्वामी दयानंद गिरि के शिष्यों ने भंडारा आयोजित किया, जिसमें स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वही सत्कर्म सफल होता है जिसमें गरीब के खून-पसीने की कमाई लगी हो। तभी उन्होंने देखा कि भंडारे के आयोजक एक गरीब वृद्धा को बाहर निकाल रहे हैं। स्वामी जी ने महिला को आदर सहित लाने को कहा। वृद्धा ने स्वामी जी से कहा कि वह भंडारे के लिये दो रुपये देना चाहती है, जिसे ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी ने तत्काल एक अनुयायी को बुलाकर कहा कि माई के दो रुपये से नमक मंगवाकर भंडारे में इस्तेमाल कर दो। खून-पसीने की ईमानदार कमाई के नमक से भंडारा भगवान का प्रसाद बन जाएगा।

सामयिक

क्या तमिलनाडु में भाजपा व अन्नाद्रमुक पार्टी का साथ जीत की गारंटी बनेगा?

अशोक भाटिया

मोबाइल : 9221232130

गत 4 अप्रैल को तमिल नववर्ष से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ राज्य में गठबंधन बनाने की घोषणा की। हालाँकि अन्नाद्रमुक ने एक समय तमिलनाडु के द्रविड़-प्रभुत्व वाले राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इसका वही प्रभाव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के समय था। पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) की अगुआई वाली पार्टी अपने पार्टी सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) के साथ नियंत्रण के लिए तीखे संघर्ष के बाद सत्ता में बनी हुई है। वर्ष 2016 से 2021 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से जुड़े रहने के कारण, ईपीएस ने भाजपा नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध का आनंद लिया। पिछले हफ़्ते चेन्नई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई घोषणा में भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि ईपीएस मौजूदा एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके गठबंधन सरकार के खिलाफ़ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं।

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है और सत्र के अंत में, लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर एक हंगामेदार बहस हुई। विधेयक का विरोध करने के लिए भाजपा का विपक्ष एक साथ आया था। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके सहित विपक्षी दल। एआईएडीएमके ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की थीं। इतना ही नहीं एआईएडीएमके के सांसदों ने राज्यसभा में भी वक्फ सुधार सरकार के खिलाफ वोट किया था। तो अब सवाल यह उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और अन्नाद्रमुक दोनों ही बहुत करीब आ गए? अमित शाह एक राजनयिक राजनेता हैं और राजनीतिक कूटनीति में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। एक राजनीतिक दल जो संसद में भाजपा का समर्थन नहीं करता है, वह राजनीतिक दल जिसने पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था, अन्नाद्रमुक, वह पार्टी जिसने एनडीए में फिर से प्रवेश किया। ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि इसने देश के सभी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक पार्टी के साथ जल्दबाजी में गठबंधन क्यों किया गया, इसका रहस्य कई लोगों के सामने नहीं आया है।

इससे पहले, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी, और अब भाजपा अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन करके चेन्नई के सिंहासन से एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा पिछले 10-12 वर्षों से तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने महसूस किया है कि द्रमुक बनाम अन्नाद्रमुक की लड़ाई में भाजपा का कोई लाभ नहीं है। भाजपा और एआईएडीएमके दोनों ने महसूस किया है कि अगर वे डीएमके को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। यही कारण है कि अमित शाह ने खुद चेन्नई में घोषणा की कि भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन राजनीतिक उदासीनता से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन बनाने में एक बड़ी बाधा थे। अन्नामलाई खुद एक जुझारू नेता हैं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने डीएमके सरकार के खिलाफ लड़ते हुए पार्टी में जान डाल दी और पार्टी की नींव मजबूत की। जहां भाजपा से कोई नहीं पूछता, भाजपा से कोई नहीं पूछ रहा है, भाजपा का कोई कैडर नहीं। अन्नामलाई ने ऐसे राज्यों में भाजपा के वोट शेयर को तीन से 11 प्रतिशत तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए अन्ना मलाई के प्रदर्शन को नजरअंदाज करना और उन्हें पद से हटाना मुश्किल था। अन्नामलाई एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वे युवा हैं। वर्ष 2019 में, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपने दमदार काम से मोदी-शाह का दिल भी जीत लिया। उनके काम को देखते हुए उन्हें तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सत्ताधारी डीएमके सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। वे स्टालिन सरकार को परेशान करते रहे।

स्पष्ट है कि सबको लग रहा था बीजेपी तमिलनाडु में 2026 का विधानसभा चुनाव अन्ना मलाई के नेतृत्व में लड़ेगी। यह भी चर्चा थी कि अन्ना मलाई आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सभी ने महसूस किया कि राजनीति में ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने रोटी पलट दी। अचानक अन्ना मलाई को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। शीर्ष नेतृत्व को यकीन था कि द्रमुक के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा जब तक कि उन्हें राज्य अध्यक्ष के पद से हटा नहीं दिया जाता। इसलिए पार्टी ने उनके स्थान पर नयनार नागेंद्र को नियुक्त किया और तुरंत भाजपा-द्रमुक गठबंधन के गठन की घोषणा की। 64 वर्षीय नयनार नागेंद्रन ने 12 अप्रैल को भाजपा के तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। नागेंद्रन एक मृदुभाषी व्यक्तित्व हैं। वे दक्षिण तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह अन्ना मलाई की तरह आक्रामक नहीं हैं। तो पार्टी के एजेंडे को कैसे लागू किया जाएगा? गठबंधन भाजपा एआईएडीएमके नेताओं की बातों को स्वीकार कर गठबंधन चलाना चाहती है। स्टालिन सरकार को हराना ही भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन के सामने एकमात्र एजेंडा है।

लोकसभा चुनाव के मामले में तमिलनाडु पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा ने कर्नाटक में पैठ बनाई, लेकिन केरल और तमिलनाडु में ज्यादा पैठ नहीं बना सकी, और अब, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने पार्टी विस्तार का एजेंडा तैयार करने के लिए अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन किया है।भाजपा ने तमिलनाडु में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 11 फीसदी वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार सांसद नहीं चुना गया था।

लोकसभा चुनाव के मामले में तमिलनाडु पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा ने कर्नाटक में पैठ बनाई, लेकिन केरल और तमिलनाडु में ज्यादा पैठ नहीं बना सकी, और अब, 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने पार्टी विस्तार का एजेंडा तैयार करने के लिए अन्नाद्रमुक को फिर से गठबंधन किया है।भाजपा ने तमिलनाडु में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को 11 फीसदी वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार सांसद नहीं चुना गया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई भी हार गए थे। भाजपा आलाकमान ने महसूस किया कि पार्टी का तमिलनाडु में कोई बड़ा आधार नहीं है और अपने दम पर चुनाव लड़ना लाभदायक नहीं है।

जैसे ही एक पुराने सहयोगी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार पार्टी में जोर पकड़ने लगा, अन्नाद्रमुक पार्टी, जिसने भाजपा छोड़ दी थी, को फिर से भाजपा द्वारा दरकिनार कर दिया गया। संसद सत्र के अंत में, एआईएडीएमके नेता दिल्ली गए और अमित शाह के साथ बातचीत की और अमितभाई भाजपा-अन्नाद्रमुक गठबंधन की घोषणा करने के लिए चेन्नई गए। 2024 के लोकसभा चुनावों में, द्रमुक सांसदों ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। द्रमुक को 46.9 प्रतिशत वोट मिले। यह 1991 के बाद से द्रमुक द्वारा सबसे अधिक वोट शेयर था। वर्ष 2024 में, भाजपा ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ा, लेकिन हर जगह हार गई। भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनावों में 3.6 प्रतिशत, 2024 में 5.5 प्रतिशत वोट मिले। 2009 में, इसे 2.3 प्रतिशत वोट और 2004 में 5.1 प्रतिशत वोट मिले। द्रमुक के पास अन्नाद्रमुक और भाजपा की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है। स्टालिन के पास पलानीस्वामी की तुलना में बड़ा समर्थन आधार है, लेकिन उन्हें सत्ता विरोधी लहर से भी पीड़ित होने की संभावना है। तमिलनाडु में, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को महत्व दिया है। डेढ़ साल के अंतराल के बाद, भाजपा और अन्नाद्रमुक ने गठबंधन में फिर से प्रवेश किया है।

हाल ही में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) नेतृत्व का मानना रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके का मुकाबला करने के लिए भाजपा के पास मजबूत कैडर बेस की कमी है। भाजपा का मानना है कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले स्टालिन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दे बनाने में एक ताकत के रूप में काम करेगा।संघ के लिए द्रविड़ मतदाता अब द्रविड़ पार्टियों के पक्ष में चुनावी यथास्थिति में विश्वास नहीं करता। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, अब आजीविका, काम के अवसर और भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे हैं, और हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ भावनाओं का भड़कना भी बड़ा मुद्दा है। ज्ञात हो कि किसी समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है, एआईएडीएमके की शक्तिशाली नेता थीं। मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। 25 मार्च, 1989 की घटना ने विधानसभा में भारी हंगामा किया था। हंगामा मच गया। उस दिन राज्य का बजट पेश किया जाना था। हालांकि, जैसे ही विपक्ष की नेता जयललिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवैध कार्रवाई की है, न केवल उनके फोन टैप किए जा रहे थे, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच खींचतान शुरू हो गई। किसी ने जयललिता की साड़ी खींची, किसी ने उसके बाल खींचे। एक ऐसी घटना जिसने संसदीय लोकतंत्र को काला कर दिया। जयललिता ने संकोच नहीं किया। उसने दृढ़ता से कहा, आज मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। अगली बार जब मैं सदन में कदम रखूंगी, मुख्यमंत्री के रूप में.... जयललिता दो साल बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सदन में दोबारा पहुंची हैं। उसने अपनी बात सच कर दी। 1991 से 2016 तक, वह 14 साल से अधिक यानी 5238 दिनों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं।

नजरिया

पश्चिम बंगाल में हिन्दू होना गुनाह क्यों?

सोनम लववंशी

मोबाइल : 70008 54500

घर जले। माँ रोई। बेटियां डर से छिप गईं। बच्चे सवाल कर रहे हैं-पापा, हमारा कसूर क्या था? और पापा चुप हैं, क्योंकि जवाब सरकार के पास नहीं है। जवाब अदालतों के पास नहीं है। जवाब मीडिया के पास नहीं है। जवाब धर्मनिरपेक्षता' की नकली माला जपने वालों के पास नहीं है। यहां कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिन्दू हैं और वो बंगाल में हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान से जो तस्वीरें आई हैं, वो केवल एक हिंसा की कहानी नहीं हैं, वो उस साजिश का पर्दाफाश हैं, जो सालों से बहुसंख्यकों के खिलाफ बुना जा रहा है। भीड़ आई, घर जलाए, मंदिर तोड़े, मां-बहनों की चूड़ियां टूटीं, और पीछे सिर्फ दर्द और खामोशी रह गई। पुलिस आई नहीं और जब आई, तो पहले पीड़ितों को धमकाया, फिर एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। कुछ जगह तो रिपोर्ट लिखने के बजाय कहा गया कि चुपचाप गांव छोड़ दो। ऐसे में सवाल यही है क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनता की सरकार' है?

ममता बनर्जी, आप चिल्ला-चिल्लाकर 'शांति' की अपील कर रही हैं। लेकिन शांति की कीमत कौन चुका रहा है? हिन्दू। हर बार हिन्दू! आपके राज्य में मंदिर जलते हैं, हिन्दू घर उजड़ते हैं, और आपकी सरकार उन्हें ही संदिग्ध मानती है। आप मस्जिदों की सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात करती हैं, लेकिन मंदिर की दीवारों पर कालिख पोतने वालों को गुमनाम भीड़ बता देती हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान, सुति और समशेरगंज की राख से उठती यह कहानी कोई एक दंगे की दास्तां नहीं है। यह उस पूरे तंत्र का चीरहरण है, जो बहुसंख्यकों की पीड़ा को 'प्रिविलेज' बताकर उन्हें चुप रहना सिखा रहा है। इस देश में अल्पसंख्यक अधिकारों की ढाल इतनी मोटी हो गई है कि उसमें बहुसंख्यकों की चीखें दबकर मर जाती हैं। तभी तो कहीं कोई दो सिरफिरे मस्जिद की छत पर चढ़ जाएं, तो पूरा देश 'फासीवाद' का हल्ला मचाने लगता है। लेकिन जब दर्जनों हिन्दू परिवारों को उनके ही घरों से खदेड़ दिया जाए, तो वही देश चुप हो जाता है। क्योंकि यहां 'हिन्दू होना' अब अपराध बन चुका है। क्योंकि यहां सेक्युलरिज़्म का मतलब है, मुस्लिम की सुनो, हिन्दू को सहने दो। धुलियान में सिर्फ घर नहीं जले हैं। वहां न्याय जला है। वहां संविधान जला है। वहां इंसानियत की लाशें बिछी हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को कोने में दबा दिया, जैसे यह कोई छोटी-मोटी लड़ाई हो। हकीकत यह है कि यह 'जनसंहार' था। सजा सिर्फ एक चीज़ की मिली और वह थी भगवा पहचान की। एक हिंदू मां अपने पाँच साल के बेटे को गोदी में लेकर भागी थी, नंगे पांव, धूप में, एक बोरी में

अपने बचे हुए कपड़े और देवी की टूटी हुई मूर्ति लेकर। क्या आपने उसकी आंखों में झांका है? क्या आपने उस बच्चे से पूछा कि वो अब किस स्कूल में जाएगा? या उसका बचपन किस राख से खेलते बीतेगा? और ये सिर्फ धुलियान नहीं। बीरभूम, कूचबिहार, मालदा हर जिले में यही कहानी दोहराई जा रही है। हर जगह हिन्दू परिवार पलायन कर रहे हैं, जैसे 1947 फिर से लौट आया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब 'देश बंट नहीं रहा, देश बंटा हुआ' है-तुष्टिकरण और चुप्पी में। जिस तरह ममता सरकार ने एक विशेष वर्ग को खुली छूट दे रखी है, वह संविधान का नहीं, कट्टरता का शासन है। 'जय श्रीराम' कहने पर जेल, लेकिन धार्मिक नारों के नाम पर हिंसा करने वालों को संरक्षण-क्या यही आपकी तृणमूल इंसाफ है? यह प्रश्न सिर्फ बंगाल का नहीं है। यह प्रश्न भारत के हर कोने का है। अगर आज बंगाल में हिन्दू पर हमले होते हैं और आप चुप रहते हैं, तो कल यही आग महाराष्ट्र में जलेगी, परसों यूपी में, और फिर आपके दरवाजे तक आएगी। तब मत कहिएगा-हमें पता नहीं था। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपको सब पता है। बस आप डरते हैं। या शायद आप इतने 'सभ्य' बन चुके हैं कि असलियत को देखने की ताकत नहीं बची।

बंगाल का रक्तरंजित इतिहास नया नहीं है। 1946 का नोआखाली, 1971 का पलायन, 2013 का कैनिंग, 2021 का चुनाव बाद का नरसंहार हर बार यही कहानी दोहराई गई है। और हर बार वही चुप्पी। वही साज़िश। वही पीड़ा। 2021 से अब तक सांप्रदायिक हिंसा की 137 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकांश में एक विशेष समुदाय को बचाया गया और दूसरे को निशाना बनाया गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा से पहले शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकला, जिसमें वक्फ की संपत्ति हमारी है जैसे नारे लगे। फिर 30 से ज्यादा मोहल्लों में आगजनी शुरू हो गई। वैसे ये समस्या सिर्फ ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, बल्कि उस पूरे राष्ट्र की भी है जो इस अन्याय पर मौन है। सोशल मीडिया पर जरा भी हिंदू हित की बात करो, तो 'राइट विंग' की मोहर लग जाती है। ऐसे में देश को तय करना होगा कि क्या वह अपने मूल धर्म और संस्कृति को सिर्फ वोटबैंक की राजनीति के आगे झुकाकर देखेगा, या फिर ग़लत को ग़लत कहने का साहस करेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम पूछें-धुलियान की राख में दबी वो चीख़ें कौन सुनेगा? वो औरतें जो आधी रात को बच्चों को लेकर भागीं, उनका अपराध क्या था? जो सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा न दे सके, वह किस नैतिकता से शासन करती है? और क्या इस देश में अब भी हिंदू होना एक अपराध है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं। जिन्हें आप मुखर स्वर दीजिए, वरना याद रखिएगा जब आपकी बारी आएगी, तब भी कोई नहीं बोलेगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कनाडाई विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अमेरिका की यात्रा न करने की चेतावनी

हैलीफैक्सै। कनाडाई विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने अपने सदस्यों को अमेरिका की अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी है।

'कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स' ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा बनाए गए राजनीतिक माहौल और कुछ कनाडाई नागरिकों को सीमा पार करने में कठिनाइयों का सामना करने की खबरों के कारण मंगलवार को नई चेतावनी जारी की।

संगठन का कहना है कि ऐसे शिक्षाविदों को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए जो उन देशों से आते हैं जिनके अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध तनावपूर्ण हैं, या जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आलोचनात्मक राय व्यक्त की है।

चेतावनी में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर पहचान वाले शिक्षाविदों और उन शोधकर्ताओं को आगाह किया गया है, जिनका अनुसंधान कार्य अमेरिकी प्रशासन की मौजूदा नीतियों के विरोधाभासी माना जा सकता है।

जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही विदेशियों को सात दिनों से अधिक समय के लिए हिरासत या प्रोसेसिंग सेंटर में भेजे जाने की खबरें सुर्खियां बन रही हैं।

कनाडा सरकार ने हाल ही में अमेरिका यात्रा को लेकर अपने यात्रा परामर्श में नागरिकों को चेतावनी दी है कि अमेरिका की सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी उनसे कड़ी पूछताछ कर सकते हैं और अगर उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया, तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है।

स्वागत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अमरावती हवाई अड्डे और यात्री उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करने के बाद गर्मजोशी से स्वागत किया किया।

'करप्शन की करतूत को भी कुर्बानी का ताबूत' बना कर घूमती है कांग्रेस : नकवी

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले का हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ''करप्शन (भ्रष्टाचार) की करतूत को भी कुर्बानी का ताबूत'' बना कर घूमती है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन कांग्रेस के लोगों का खुद को पीड़ित दिखाने का रिवाज बन गया है।

नकवी ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस करप्शन की करतूत को भी कुर्बानी का ताबूत बना कर घूमती है।'' उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर दावा किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए सुधार से कुछ लोग बौखला गए हैं।

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ बैठक के बाद बीएनपी ने असंतोष जताया

ढाका/भाषा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बुधवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ अपनी बैठक पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी इस साल के अंत तक चुनाव की मांग करती है।'प्रथोम आलो' अखबार की खबर में कहा गया है कि बीएनपी महासचिव के नेतृत्व में सात सदस्यीय ने सरकारी अतिथि गृह जमुना में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से मुलाकात की।

फिल्म 'वध 2' की शूटिंग पूरी

मुंबई/एजेन्सी

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर फिल्म 'वध 2' की शूटिंग पूरी हो गयी है। वर्ष 2022 में प्रदर्शित थ्रिलर फिल्म वध की अगली कड़ी वध 2 की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है।एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की दमदार जोड़ी इस फिल्म में नजर आएगी। वध 2 का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है और इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग के प्रोडक्शन हाउस लव फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। संजय मिश्रा ने कहा,वध सिर्फ़ एक फिल्म नहीं थी, वो एक ऐसा सिनेमा अनुभव था जो हमारे साथ-साथ दर्शकों के दिल में भी उतर गया। अब जब वो एक फ्रैंचाइज़ी बन रही है, तो ये एक साथ विनम्रता और उत्साह से भर देने वाला है। जसपाल के निर्देशन में एक बार फिर काम करना वाकई प्रेरणादायक रहा, उनकी सोच हर सीन को एक गहराई दे देती है। नीना गुप्ता ने कहा,ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं जिनकी अपनी एक अलग आवाज़ होती है।

जसपाल सिंह संधू के पास सच्चाई और तनाव को पकड़ने की जो नजर है, वो उन्हें एक बेहतरीन कहानीकार बनाती है। मुझे गर्व है कि मैं एक बार फिर इस सफर का हिस्सा बनी हूं और दर्शकों को वध 2 में हमारे द्वारा रची गई दुनिया दिखाने का बेसब्री से इंतज़ार है। निर्देशक जसपाल सिंह संधू ने कहा,संजय जी और नीना जी के साथ दोबारा काम करना मेरे लिए एक तोहफे जैसा है। मैं लव फिल्म्स का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस विज़न पर भरोसा किया और पूरे दिल से इसका साथ दिया। अब बस इंतज़ार है उस पल का जब दर्शक हमारी इस दुनिया का हिस्सा बनेंगे। वध 2 इस साल रिलीज़ होगी। इस साल की शुरुआत में वध 2 की टीम ने प्रयागराज में आयोजित शुभ महाकुंभ में संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर अपनी फिल्म के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लिया था।

'सुपर्ब फेयरी-रेंस' पक्षियों के गीतों में उनके व्यक्तित्व के सुराग छिपे होते हैं

एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया)। जब हम पक्षियों के गीतों के बारे में सोचते हैं तो हम अकसर सुबह की सैर के दौरान एक खुशनुमा 'धुन' की कल्पना करते हैं। हालांकि, पक्षियों के लिए गीत पृष्ठभूमि संगीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वे एक साथी को आकर्षित करने और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए करते हैं।

लेकिन क्या होगा अगर कोई गाना गायक के व्यक्तित्व के बारे में कुछ गहरा खुलासा कर सके?'रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस' में डायने कोलोम्बेली-नेग्रेल और उनके सहकर्मियों द्वारा प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा हो सकता है।

शोध अंतराल को पाटना

पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए गाने की जटिलता अलग-अलग होती है, कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में अधिक जटिल धुनें बनाते हैं। इस तरह के अंतर अकसर आनुवांशिक गुणवत्ता, आयु या स्वास्थ्य में व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। आज तक के अधिकांश शोध नर पक्षियों पर केंद्रित रहे हैं और बहुत कम अध्ययनों ने इस बात को परखा है कि पक्षियों में गाने की जटिलता उनके व्यक्तित्व से कैसे संबंधित है। नया अध्ययन इसी शोध अंतराल को संबोधित करता है

डायने कोलोम्बेली-नेग्रेल और उनके सहयोगियों ने एक छोटी ऑस्ट्रेलियाई गाने वाली चिड़िया जंगली 'सुपर्ब फेयरी-रेंस' (मैलुरस साइनेस) का अध्ययन किया, जो अपने चमकदार पंखों और गाने की जटिल कला के लिए जानी जाती है। रोचक बात यह है कि इन प्रजातियों में दोनों ही नर एवं मादा पक्षी जटिल गीतों को गाना सीखते हैं। यह उन्हें नर और मादा दोनों में गीत की जटिलता और व्यक्तित्व के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक अच्छा उदाहरण बनाता है। शोधकर्ताओं ने जंगली 'सुपर्ब फेयरी-रेंस' को पकड़ा और उनके व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए कैद में रखा। विशेष रूप से, उन्होंने पक्षियों को एक नए वातावरण में रखकर उनका आकलन किया। उन्होंने देखा कि ये पक्षी कहां-कहां गए और उन्होंने पर्यावरण के बारे में कितनी खोज की। शोधकर्ताओं ने आईने का उपयोग करके उनकी आक्रामकता का भी परीक्षण किया, क्योंकि पक्षी अकसर अपने प्रतिबिंब को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने पक्षियों की गीत की जटिलता (प्रति गीत तत्व के प्रकार और प्रति गीत आलाप) का आकलन करने के लिए कई महीनों तक उनके गीतों को रिकॉर्ड किया।

आक्रामकता बनाम खोज

शोधकर्ताओं ने पाया कि लिंग या जीवन अवस्था से परे जो पक्षी अधिक खोजी प्रवृत्ति के थे, उनमें कम खोजी प्रवृत्ति वाले पक्षियों की तुलना में प्रति गीत अधिक तत्व थे। साथ ही, अधिक आक्रामक पक्षियों ने कम आक्रामक पक्षियों की तुलना में कम आलाप वाले गीत गाए, जिन्हें रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका अध्ययन दर्शाता है कि नर और मादा दोनों ही अपने गीतों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सकते हैं।

यह सवाल भी उठता है कि पक्षी अपने गीत किससे सीखते हैं। 'सुपर्ब फेयरी-रेंस' पक्षी के मामले में नन्हे पक्षी अपने माता पिता के साथ साथ प्रजाति के अन्य सदस्यों से ये गीत सीखते हैं। इसके अलावा अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यक्तित्व और गीत की जटिलता के बीच का संबंध जीवन के विभिन्न चरणों के बीच बदल सकता है।

बेहतरीन अभिनेता हैं रणबीर कपूर : इमरान हाशमी

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म 'ग्राउंड जीरो' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच इमरान हाशमी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात की। उन्होंने बॉलीवुड में उभरती प्रतिभाओं के बारे में खुलकर बात की और रणबीर कपूर को उनकी जनरेशन का बेस्ट स्टार बताया। उन्हें मौजूदा पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बताते हुए हाशमी ने 'एनिमल' में रणबीर के अभिनय की तारीफ की। रणबीर की अभिनय क्षमता की तारीफ करते हुए इमरान ने कहा, मैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा- यह शोर से भरा एक इको चैंबर है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन रणबीर कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं, जिनकी मैं वाकई प्रशंसा करता हूं। मुझे एनिमल में उनका अभिनय पसंद आया। कई युवा अभिनेता बेहतरीन काम कर रहे हैं और स्क्रीन पर नए नजरिए को ला रहे हैं।

संदीप रेड्डी वांगा की एक्शन-थ्रिलर में रणबीर ने रणविजय सिंह की भूमिका निभाई, जो अपने पिता की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता है। जब उसके पिता की हत्या का प्रयास किया जाता है तो दुश्मनों से लड़ने के लिए वह आगे आता है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अभिनेता बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं। इमरान के लेटेस्ट प्रोजेक्ट 'ग्राउंड जीरो' की बात करें तो, फिल्म में वह बीएसएफ कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने गाजी बाबा को मारने के लिए ऑपरेशन को लीड किया था। इस मिशन को पिछले 50 वर्षों में बीएसएफ के बेस्ट ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है।

फिल्म 'ग्राउंड जीरो' में दुबे की भूमिका को लेकर इमरान हाशमी ने बताया, जब कोई अभिनेता इस तरह की भूमिका निभाता है, तो हमेशा एक शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल होता है। शारीरिक रूप से मुझे एक अनुशासित बॉडी लैंग्वेज अपनानी पड़ी। जब आप एक कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहे होते हैं, तो व्यवहार महत्वपूर्ण हो जाता है।

उन्होंने कहा, मुझे अपने शरीर पर भी काम करना पड़ा- वेट ट्रेनिंग, आहार में बदलाव, कैलोरी में वृद्धि- उनकी जनरेशन के बेस्ट स्टार भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से, मैंने बीएसएफ अधिकारियों से बात की और उनके हाव भाव को समझने की कोशिश की, ताकि मैं ऑपरेशन के दौरान उनकी मानसिक स्थिति, उनके परिवार की स्थिति और इस तरह के हाई रिस्क वाले पेशे से होने वाले भावनात्मक तनाव को समझ सकूं। तेजस देओस्कर के निर्देशन में बनी 'ग्राउंड जीरो' इसी साल 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

'कोस्टाओ' का टीजर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता नवाजउद्दीन सिद्दिकी की आने वाली फिल्म 'कोस्टाओ' का टीजर रिलीज हो गया है। नवाजुद्दीन जल्द ही फिल्म 'कोस्टाओ' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे।

इस फिल्म का निर्देशन सेजल शाह ने किया है। निर्माताओं ने 'कोस्टाओ' का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें नवाजउद्दीन का धाकड़ अवतार दिख रहा है। फिल्म 'कोस्टाओ' एक हाई-ऑक्टेन क्राइम ड्रामा है, जो गोवा के सबसे बड़े तस्कर से लोहा लेने वाले कस्टम अधिकारी के जीवन से प्रेरित है। इस फिल्म में नवाजउद्दीन कस्टम अधिकारी कोस्टाओ फर्नांडीज की भूमिका में नजर आएंगे। नवाजउद्दीन के साथ इस फिल्म में प्रिया बापट और किशोर कुमार हुली जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म ओटीटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है।

गायिका किंजल दवे ने किए महाकाल के दर्शन

उज्जैन/एजेन्सी

गायिका और अभिनेत्री किंजल दवे बुधवार को उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के द्वार पहुंचीं, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुईं। गुजराती गायिका महाकाल की भक्ति में डूबी नजर आईं। किंजल दवे ने नंदी हॉल में बैठ भगवान महाकालेश्वर की साधना की। चांदी द्वार से दर्शन पूजन कर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। श्रीराम पुजारी ने पूजन सम्पन्न करवाया। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के बाद खुशी जाहिर की। दर्शन-पूजन के पश्चात गायिका ने मंदिर समिति और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह बाबा के मंदिर पहली बार आई हैं और उन्हें अच्छे से दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर काफी खुश हूं। मैं यहां पहली बार आई हूं, पहली बार भस्म आरती में शामिल होकर काफी खुशी मिली है। बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। पुजारी श्रीराम ने गायिका को नीले रंग का पटका प्रसाद स्वरूप भेंट किया।

बता दें, किंजल दवे महाकाल पर भक्ति गीत 'जिसे मोह न माया जाल का वो भक्त है महाकाल का' भी गा चुकी हैं। कई गुजराती फिल्मों में गाने गा चुकीं किंजल दवे का जन्म गुजरात के पाटण जिले में हुआ है। गायन के साथ ही किंजल अभिनय में भी निपुण हैं, वह कुछ फिल्मों में अभिनय भी कर चुकी हैं। किंजल दवे गायिका और अभिनेत्री के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। महाकाल के दर्शन को उज्जैन पहुंचने वाले सितारों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। 30 मार्च को अभिनेता विंदु दारा सिंह महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में भी शामिल हुए। उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे।

महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती लोकप्रिय है और इसमें शामिल होने के लिए दुनियाभर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। भस्म आरती का काफी पौराणिक महत्व है। आरती में श्मशान से लाई गई चिता के भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। चिता भस्म के अलावा इसमें गोहरी, पीपल, पलाश, शमी और बेल के लकड़ियों की राख को भी मिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती के दौरान महिलाएं सिर पर घूंघट या ओढ़नी डाल लेती हैं।

फिल्मकार बनना चाहते थे अर्जुन कपूर

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने बताया है कि वह फिल्मकार बनना चाहते थे। अर्जुन कपूर ने हाल ही में बताया कि उनका सपना कभी सिर्फ एक स्टार बनने का नहीं था, बल्कि वह फिल्में बनाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता बोनी कपूर रूप की रानी चोरो का राजा बना रहे थे, तब ही उनके भीतर ये चिंगारी जली। उन्होंने कहा, सिनेमा का जादू ही मुझे आकर्षित करता है। मुझे कोरियन फिल्में और यूरोपियन सिनेमा बहुत पसंद है। मैं फिल्ममेकर बनना चाहता था। अर्जुन कपूर ने कहा, रूप की रानी चोरों का राजा उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। मैं मंत्रमुग्ध था और फिल्मों की खुशी मेरे साथ रह गई। मैं हमेशा फिल्म के बनने की प्रक्रिया जानना चाहता हूं और उसी में मुझे असली खुशी मिलती है। अर्जुन कपूर की वह बात सबसे ज़्यादा दिल को छू गई, वो थी उनका भारतीय क्रिएटर्स को दिया गया प्यार और सम्मान। आर बल्कि और संजय लीला भंसाली से लेकर द फ़ैमिली मेन और पंचायत के मेकर्स तक, अर्जुन ने उस देसी सिनेमा को सराहा जो दिल से बनता है। उन्होंने आजकल के ट्रेलर्स की भी आलोचना की जो बहुत कुछ पहले ही बता देते हैं। उन्होंने उन ट्रेलर्स की तारीफ की जो सस्पेंस बनाए रखते हैं, जैसे पद्मावत, एनिमल, और बाजीराव मस्तानी के ट्रेलर्स। अर्जुन कपूर ने कहा, मैं ट्रेलर में फिल्म की एनर्जी महसूस करना चाहता हूं। एनिमल का टीज़र और ट्रेलर बहुत दमदार था! पद्मावत का ट्रेलर खूबसूरत है। सिर्फ विजुअल्स दिखते हैं। वो डायरेक्टर का ट्रेलर है। बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर भी कमाल का था।

मैंने रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दिया है : सैयामी खेर

नई दिल्ली/एजेन्सी

अभिनेत्री सैयामी खेर ने अपने करियर को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की। इस दौरान खेर ने बताया कि वह अपने काम पर फोकस करती हैं और रिजल्ट की फिक्र नहीं करती हैं। अभिनेत्री का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, जहां आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। यह पूछे जाने पर कि वह लगातार आगे बढ़ रही इंडस्ट्री में अपेक्षाओं के दबाव को कैसे मैनेज करती हैं, सैयामी ने बताया, दबाव कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन जब आपका ध्यान रिजल्ट के बजाय काम पर होता है, तो सांस लेना आसान हो जाता है। मैंने रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दिया है और प्रक्रिया को महत्व देना शुरू कर दिया है। अभिनेत्री ने आगे बताया, मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं, जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। ऐसे किरदार निभाना पसंद है, जो चुनौती देते हैं और मैं अपने काम से ही इस प्रेशर को मैनेज करती हूं। मैंने अभिनय की दुनिया में भी कदम इसी वजह से रखा था, क्योंकि मुझे यह पसंद है। साल 2015 से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात से होता है? सैयामी ने कहा, इसकी अनिश्चितता।

अभिनेत्री ने कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री की अनिश्चितता से हैरान हूं, जहां आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, रिजल्ट की कभी गारंटी नहीं होती। आप किसी चीज में अपना दिल, आत्मा, मेहनत सब कुछ लगा सकते हैं, फिर भी निश्चित नहीं है कि परिणाम क्या होगा। लेकिन यही चीज उसे जीवंत और मैजिकल बनाए रखती है। उन्हें यह भी आश्चर्य होता है कि समय की पाबंदी को एक रेयर क्वालिटी के रूप में कैसे देखा जाता है। सैयामी ने कहा, एक और बात जो मुझे वाकई हैरान करती है, वह यह कि समय की पाबंदी को एक रेयर क्वालिटी की तरह देखा जाता है। मेरे लिए, समय की पाबंदी ऐसी चीज नहीं है जिसकी सराहना की जानी चाहिए - यह सम्मान का एक बुनियादी संकेत है। अनुशासन को अक्सर कम आंका जाता है। सैयामी की हालिया रिलीज फिल्म 'जाट' है, जिसमें वह सनी देओल और रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका में हैं। 10 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 'जाट' में रेजिना कैसेंड्रा भी अहम किरदार निभा रही हैं। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने फिल्म में 'टच किया' गाने पर डांस किया है। गोपीचंद मलिनेनी के निर्देशन में बनी 'जाट' का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने मिलकर किया है। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई है।

अदिवी सेष स्टारर 'मेजर' जापान में रिलीज होगी

मुंबई/एजेन्सी

सई एम मांजरेकर और अदिवी सेष की फिल्म 'मेजर' जापान में रिलीज होगी। फिल्म मेजर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मुकाम हासिल किया है। इस बहुप्रशंसित बायोपिक एक्शन ड्रामा को अब जल्द ही जापान में प्रदर्शित किया जाएगा।

जापान स्थित भारतीय दूतावास इस खास स्क्रीनिंग का आयोजन करेगा, जिसमें फिल्म जापानी सबटाइटल्स के साथ दिखाई जाएगी। यह विशेष स्क्रीनिंग 29 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:50 बजे तक आयोजित की जाएगी और यह नि:शुल्क होगी, हालांकि इसके लिए पूर्व-पंजीकरण आवश्यक है। अदिवी सेष, जिन्होंने फिल्म में भारतीय वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका निभाई थी, ने इस रोमांचक खबर को एक्स पर साझा किया।

यह फिल्म न केवल एक सिनेमाई उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक सीमाएं पार कर दुनिया तक उसकी गूंज पहुंचाती है। जापानी दर्शकों के लिए, यह फिल्म एक साहसी भारतीय सैनिक की कहानी होगी, जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान नागरिकों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। जहां अदिवी सेष ने एक वीर सिपाही का जीवन चित्रित किया, वहीं सई मांजरेकर ने उनकी ऑन-स्क्रीन पत्नी की भूमिका निभाई। युवा प्रेम से लेकर बलिदान और समर्थन तक, सई ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिल जीत लिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

बेंगलूरु | गुरुवार | 17-04-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. 58061/93. Regn No.:
RNP/KA/BGS/2050/2018-2020
Posted at Bengaluru PSO
Mysore Road Bengaluru-560 026.

शहर के महावीर जिनालय की बुधवार को वार्षिक वर्षगांठ मनाई गई तथा पूरी धूमधाम व विधिविधान से मंदिर के शिखर पर 18वां ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण का लाभ ललिताबाई प्रवीणकुमार विनयकुमार दांतेवाड़िया परिवार को प्राप्त हुआ।

टीम 'बर्ड आई' बनी वैभव क्रिकेट कप चैंपियन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो जेएसपीएल द्वारा आयोजित वैभव कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टीम बर्ड आई व किंग्समैन टीम के बीच मैच खेला गया। किंग्समैन टीम के मुकाबले शानदान प्रदर्शन करते हुए बर्ड आई टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार मनोज बाफना को दिया गया। वहीं, टूर्नामेंट के प्रमुख खिलाड़ी प्रतीक जैन रहे। निशांत कोठारी को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गौरव सुराना को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया।

गजानन कप क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय पोरवाल जैन समाज के युवाओं की आपसी नेटवर्किंग बढ़ाने एवं उनकी खेल प्रतिभा को उचित अवसर देने के उद्धेश्य से आयोजित गजानन कप बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घघाटन कॉक्स टाउन में हुआ। पोरवाल जैन संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 12 पुरुष, 8 महिला और 4 किशोर टीम भाग ले रही हैं।

लगातार तीन रविवार को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घघाटन प्रायोजक गजानन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अशोक गजानन परिवार ने किया। पोरवाल युवा समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में रोशन रायल्स, जियानी ब्लेजर्स, गजानन गरुड़ास, कजारी किंग्स, प्रतिभास टाइटंस, साकरिया सुल्तान्स, नरेश फ़ार्मा किंग्स, केशरी वारियर्स, जैन लाइफ स्पेस स्टार्स, राठौड़ ट्रेल ब्लेजर्स, चौहान ग्लेडियेटर्स एवं जियानी सुपर किंग्स टीम भाग ले रही है।

एमके स्टालिन से कमल हासन ने की मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से चेन्नई स्थित सचिवालय में मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन ने बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल मामले को लेकर सीएम स्टालिन को बधाई दी। मुलाकात के बाद कमल हासन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब मैं पत्रकारों से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं राज्यसभा सीट के लिए धन्यवाद देने आया हूं? इस पर मैंने जवाब दिया, जब सीट तय हो जाएगी और पार्टी में घोषणा हो जाएगी तो हम आपको धन्यवाद देने आएंगे। मैं अभी जश्न मनाने आया हूं। मैं मुख्यमंत्री को इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के मामले में मिली जीत के लिए बधाई देने आया हूं। यह हमारे लिए जितना लाभदायक है, उससे कहीं अधिक भारत के लिए लाभदायक है। हासन ने आगे कहा, मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, क्योंकि यह फैसला उनके मामले में आया है। हमें इस जीत का जश्न राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को लेकर फैसला सुनाया है कि वह विधानसभा से पारित विधेयकों को मनमाने ढंग से रोके नहीं रह सकते। तमिलनाडु सरकार, आरएन रवि पर आरोप लगाती रही है कि वे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल रवि को फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को बिना अधिकार के लंबे समय तक रोके रखा। यह 'मनमाना' रवैया है।

तमिलनाडु से 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। 2024 के संसदीय चुनावों में मक्कल निधि मय्यम पार्टी ने डीएमके के समर्थन में प्रचार कयिा था। इसलिए, ऐसा लगता है कि एक राज्यसभा सीट मक्कल नीधि मैयम पार्टी को आवंटित की जाएगी। कमल हासन के मक्कल निधि मय्यम की ओर से राज्यसभा चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। इस स्थिति में कमल हासन की आज मुख्यमंत्री एम.के. स्टालनि से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा।

मंदिर उत्सव के दौरान आरएसएस नेता की तस्वीरें प्रदर्शित करने पर विवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोल्लम/भाषा। केरल के कोल्लम जिले में मंदिर उत्सव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक के बी हेडगेवार की तस्वीरों के प्रदर्शन से विवाद हो गया है। मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) ने अपनी सतर्कता शाखा से रिपोर्ट मांगी है।

मंगलवार रात को कोल्लम पुरम उत्सव के दौरान हेडगेवार की तस्वीरें बी आर आंबेडकर और श्री नारायण गुरु जैसे प्रमुख समाज सुधारकों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शित की गईं। टीडीबी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिले में स्थित पुथियाकावु मंदिर का प्रबंधन पुरम उत्सव में ''कुडमट्टम'' के आयोजन के दौरान आरएसएस नेता की तस्वीरें प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर टीडीबी के दायरे में नहीं आता है।

कोल्लम पुरम प्रसिद्ध आश्रमम श्री कृष्णस्वामी मंदिर में वार्षिक उत्सव के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक प्रदर्शन है। टीडीबी के अंतर्गत आने वाला आश्रमम मंदिर इस कार्यक्रम का आयोजक है, लेकिन अन्य स्थानीय मंदिर भी इसमें भाग लेते हैं। टीडीबी के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, कोल्लम पुरम के दौरान आरएसएस नेता की तस्वीरें प्रदर्शित करने का मुद्दा संज्ञान में आने के बाद टीडीबी ने इस संबंध में देवस्वओम सतर्कता शाखा से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुथियाकावु मंदिर, जिसने कथित तौर पर उत्सव के दौरान आरएसएस नेता की तस्वीरें प्रदर्शित की थी, टीडीबी के तहत नहीं आता है। यह घटना कोट्टक्कल के एक मंदिर में संगीत समारोह के दौरान आरएसएस के प्रार्थना गीत के कथित गायन और जिले के कडक्कल में एक अन्य उत्सव के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की प्रशंसा में 'क्रांतिकारी गीत' गाने से संबंधित विवादों के बाद हुई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मंदिर उत्सवों के दौरान राजनीतिक प्रतीकों के प्रदर्शन के खिलाफ उच्च न्यायालय का निर्देश लागू है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने घटना की आलोचना की और आरोप लगाया कि लोगों का एक वर्ग राज्य में पूजा स्थलों का राजनीतिकरण करने का जानबूझकर प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेता सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) पूजा स्थलों के राजनीतिकरण के खिलाफ है। उन्होंने आरएसएस और माकपा दोनों से ऐसी गतिविधियों से परहेज करने का आग्रह किया।

महावीर जैन मंदिर में धूमधाम से हुआ 18वाँ ध्वजारोहण, मनाई वर्षगांठ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। शहर के महावीर जिनालय की बुधवार को वार्षिक वर्षगांठ मनाई गई तथा पूरी धूमधाम व विधिविधान से मंदिर के शिखर पर 18वां ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण का लाभ ललिताबाई प्रवीणकुमार विनयकुमार दांतेवाड़िया परिवार को प्राप्त हुआ। लाभार्थियों ने मंदिर के शिखर पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ विधिविधान से ध्वजारोहण किया। प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी की पक्षाल पूजा एवं स्नात्र पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके उपरांत सुमतिनाथ महिला मंडल द्वारा सतरभेदी पूजा का पाठ किया गया। समारोह में ट्रस्ट द्वारा लाभार्थी परिवार का विशेष सम्मान किया गया। साथ ही मंदिर के वार्षिक चढ़ावे में समाज के लोगों ने उत्साह से भाग लिया।

श्रीराम भारत की चमक और प्रकाश हैं : महेन्द्र मुणोत

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । शहर के विजयनगर में मारुति मेडिकल्स के प्रमुख एवं समाजसेवी महेन्द्र मुणोत ने सनातन परम्परा की पहचान, अखंड भारत का गौरव, महापुरुषों की मर्यादा के प्रतीक भगवान श्रीराम को समर्पित उत्सव श्रीराम नवमी धूमधाम से मनाई गई। श्रीराम और हनुमान की पूजा के साथ महेन्द्र-सुरक्षा मुणोत ने श्रीराम नवमी उत्सव मनाया। हजारों भक्तों को छाछ, कोसाम्बरी सहित भोजन प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद महेंद्र मुणोत ने अन्नप्रसाद वितरण सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुणोत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भारत की आत्मा हैं, भारत के आध्यात्म की नींव हैं। श्रीराम भारत का आत्मविश्वास हैं, भारत की विचारधारा हैं, भारत का सत्य हैं, भारतीयों का प्रेम हैं। श्रीराम भारत की चमक हैं और भारत का प्रकाश हैं। उन्होंने उपस्थित सभी जनों को भगवान श्रीराम के गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी।

भाषा साहित्य मंच की नवसंवत्सर-नवरात्रि विषयक गोष्ठी सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भाषा साहित्य मंच की अप्रैल माह की गोष्ठी नवसंवत्सर-नवरात्रि विषय पर आनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। सरिता श्रीवास्तव ने मां शारदे की वंदना की। वरिष्ठ सदस्या एवं सहसंयोजिका डॉ वत्सला किरण की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मंच की संस्थापिका अध्यक्ष डॉ उषा श्रीवास्तव ने स्वागत किया।

संगोष्ठी में डॉ. सुमन मेहरोत्रा, डॉ.वत्सला किरण, त्रिशला मिश्रा, सरिता श्रीवास्तव, डॉ शांति मोहनन, दीप्ति भारद्वाज, अर्चनासिंह रायजादा, मनीषा शर्मा, प्रवीणा कुलश्रेष्ठ, सुषमा कुलश्रेष्ठ, भगवती सक्सेना आदि ने भजन, गीत, कविता आदि की प्रस्तुति दी। सुषमा कुलश्रेष्ठ के धन्यवाद दिया। अर्चनासिंह रायजादा ने संचालन किया।

कर्नाटक में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही भाजपा, सतर्क और एकजुट रहें : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कलबुर्गी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार को गिराकर सत्ता हथियाने का प्रयास करने का बुधवार को आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से सतर्क रहने तथा आंतरिक मतभेदों को दूर कर एकजुट रहने को कहा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि ऐसी चीजों से न तो पार्टी और न ही उसका नेतृत्व डरेगा और न ही झुकेगा, बल्कि देश और देशवासियों के कल्याण के लिए आवाज उठाता रहेगा।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, आपने (भाजपा ने) देश के लिए क्या किया है? केवल ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, वे वहां की सरकारों को गिराकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में भी इसी तरह की कोशिशें की जा रही हैं। खरगे ने कहा, यहां हमारे लोगों (कांग्रेस) को सतर्क रहना चाहिए। आपके बीच चाहे जो भी आंतरिक मतभेद हों, आपको एकजुट रहना चाहिए।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी और शाह मिलकर गरीब लोगों को निगल जाएंगे। लोगों की रक्षा के लिए आपको सत्ता दी गई है। उनकी रक्षा करना आपके हाथ में है। वे (भाजपा) वहां बैठे हैं, लूट रहे हैं और दरार पैदा कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भाजपा कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश करती है, लेकिन हम न डरेंगे और न ही झुकेंगे। हम हमेशा आपके आशीर्वाद और समर्थन से लड़ेंगे। हम देश को एकजुट रखेंगे, देश का निर्माण करेंगे और भाजपा सरकार को बाहर करेंगे। खरगे यहां राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक नौकरी मेले को संबोधित कर रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और राज्य के कई मंत्री शामिल हुए।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का ध्यान ईडी, सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) का इस्तेमाल कर अन्य राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं को निशाना बनाने पर अधिक है। खरगे ने भाजपा पर देश और समाज को बांटने तथा धर्मों के बीच दरार पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। बाद में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि लोगों को उनके द्वारा सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की आलोचना करने पर आपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने हरियाणा में एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों की आलोचना की थी।

खरगे ने कहा कि गुलबर्गा (कलबुर्गी) संभाग या कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कोई एम्स अस्पताल नहीं है और उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कई पत्र लिखे हैं। बार-बार अनुरोध के बावजूद वे कलबुर्गी के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com